RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053

राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

सहायक संपादक
प्रभाकर कुमार राय/एस. एन. श्याम

संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
रंजीत कुमार 8800689555

कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट

बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह

मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार

जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334114515
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 8, अंक : 2, अक्टूबर 2020, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

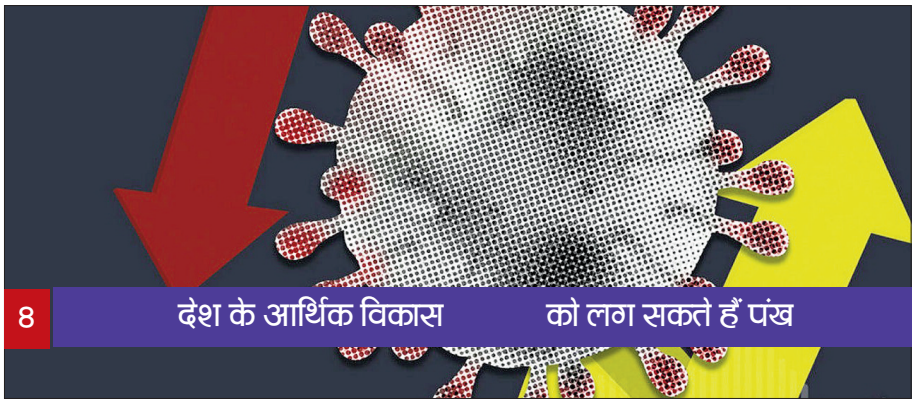

8 देश के आर्थिक विकास को लग सकते हैं पंख

नीतीश को फिर मुख्यमंत्री ... 22

फिर से रफ्तार पकड़ने लगी ... 24

रामविलास का राजनीतिक... 34

आयुर्वेद की अहमियत 36

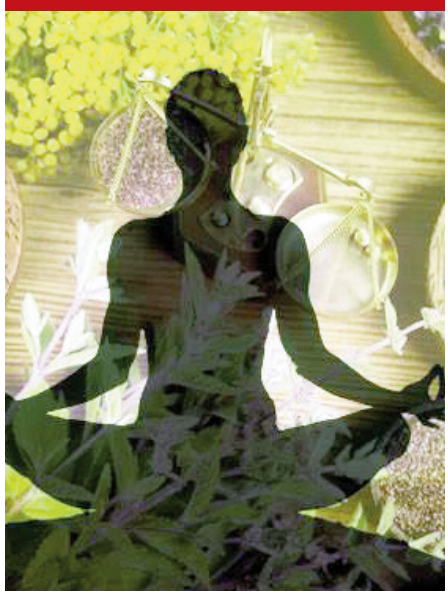

लोकतंत्र के दोराहे पर खड़ा वोटर बिहार का

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

महामारी के दौर में होने जा रहे बिहार चुनाव की ओर स्वाभाविक ही पूरे देश की निगाह लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा के महत्वपूर्ण चुनावों के ठीक पहले हो रहे इन चुनावों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ना तय है। देश गहरे संकट से गुजर रहा है। समाज में हलचल है। जनता के तमाम तबके आंदोलित हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। आंदोलनों के दबाव में एनडीए दरक रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव के नतीजे नई आंदोलनात्मक संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। रही बात चुनाव नतीजों के आकलन की तो अभी हाल तक इसे एकतरफा माना जा रहा था। नीतीश कुमार की पुनर्वापसी तय बताई जा रही थी। वजह? एक तो मोदी जी की लोकप्रियता। ऐसी धारणा बना दी गई है कि भारत में सब कुछ परिवर्तनशील है, बस मोदी जी की लोकप्रियता को छोड़कर। दूसरा तर्क यह कि जो सामाजिक-राजनीतिक समीकरण उन्हें सत्ता में लाया था, वह बदस्तूर कायम है। आश्चर्यजनक है कि यह सब उस महा आपदा के साये में होने जा रहे चुनाव के बारे में कहा जा रहा था, जिसने डबल इंजन की सरकार के डबल डिजास्टर को अभी हाल ही में दुनिया के सामने पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है। जिसने वतन लौट रहे प्रवासी बिहारी मजदूरों को खून के आंसू रुलाए हैं और अभी भी जनता का बड़ा हिस्सा आर्थिक तबाही-बाढ़-महामारी जैसे संकटों के पहाड़ से चौतरफा घिरा हुआ है। बहरहाल, चुनाव की घोषणा होने के बाद हर नए दिन के साथ यह गढ़ी गई धारणा ध्वस्त होती जा रही है। अब यह आमराय बनती जा रही है कि राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और यह संभव है कि कल तक अपराजेय माने जा रहे नीतीश कुमार इस चुनाव के सबसे बड़े लूजर साबित हों। मुकाबला आम तौर पर दोनों मुख्य गठबंधनों के बीच आमने-सामने का होगा। इसमें एलजेपी जिन जगहों पर तीसरा कोण बनाएगी, वहां ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखना रोचक होगा। कुछ छोटे जाति आधारित दल भी मैदान में हैं, पर वे वोटकटवा वाली भूमिका ही निभाएंगे। बीजेपी की दो नावों की सवारी जरूर उसे भारी पड़ सकती है। समाज में यह संदेश चला गया है कि चिराग पासवान अमित शाह के शातिर खेल के मोहरे हैं। ऐसे में बीजेपी और नीतीश के सामाजिक आधार के बीच अविश्वास गहरा सकता है और अगर यह प्रतिक्रिया वोटों में व्यक्त हुई तो न सिर्फ उन सीटों पर जहां महागठबंधन के खिलाफ एलजेपी और नीतीश आमने सामने हैं, बल्कि वहां भी जहां महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी है, महागठबंधन के पक्ष में आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं। वैसे तो संघ-बीजेपी की विकास यात्रा में अनेक कारकों और परिस्थितियों का योगदान है, पर कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ने के लिए गैर-वामपंथी विपक्ष की धारा ने 60, 70, 80 के दशक में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर उनसे जो बार-बार हाथ मिलाया।

बिहार विकास में तेजी से आगे बढ़ेगा : नीतीश

बिहार में विकास की नयी कहानी लिखी जा रही है। इसका गवाह देश ही नहीं पूरी दुनिया भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि बिहार की तरक्की एवं उन्नति करना हमारा दायित्व है और जल्द ही बिहार विकास में तेजी से आगे बढ़ेगा ताकि इस प्रदेश के वासी अपने कर्म से बिहारी कहलाएं और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। बिहार प्रतिदिन विकास की नई गाथा लिख रहा है। 15 वर्षो के अपने शासनकाल में सड़क बनायी, बिजली उपलब्ध कराया गांव से लेकर शहरों तक, विद्यालय भवनों के साथ वहां बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करायी, अस्पतालों में दवा उपलब्ध करवाया। वर्तमान सरकार इंसाफ के साथ राज्य के चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चुनावी रणनीति बनाने में सभी जुटे हुए हैं, सभी सत्ता को पाना चाहते हैं मगर नीतीश कुमार के साथ उनका विकास सबसे अहम मुद्दा उनको सबसे आगे की श्रेणी में खड़ा करता है। कोरोना के चलते आज क्या स्थिति हो गई है। किसी एक जगह की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे बिहार में कोरोना का काफी प्रभाव है। सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। मैं इस पर काम करने के लिए सभी चिकित्सकों को तथा इस पेशे से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को, नर्सेज को और जो लोग उनका सहयोग करते हैं, हमारे प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के लोगों को, जिन्होंने साथ दिया है उसका अभिवादन करके, उनलोगों से मिलकर नीतीश कुमार हौसलाअफजाई करते रहते हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति

मुख्यमंत्री कहते हैं इस विषम परिस्थिति में सबलोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे राहत मिले, इससे छुटकारा मिले। आप सभी को पता है अपने देश में इसकी चर्चा मार्च से ही हुई है और हमलोगों ने 13 मार्च को पहली मीटिंग की थी। 16 मार्च को विधानमंडल का सत्र था, सर्वदलीय बैठक कर सबलोगों से बात करके 16 मार्च को ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो स्थिति आ रही थी उसको देखते हुए ही हमलोगों ने बिहार में आंशिक लॉकडाउन का निर्णय 23 मार्च को ले लिया था लेकिन 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया। चार चरणों में पूरे देश में लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने लागू किया। इसके बाद अनलॉक एक और दो लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर से अनलॉक-5 लागू किया गया। बिहार सरकार पूरे तौर पर केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं उसका पालन कर रही है। उसके अलावा जो भी आवश्यकता है उसे ध्यान में रखते हुए जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोई और रिस्टिक्शन लागू करना पड़ता है, तो उसको किया जाएगा। सबलोग अपने स्तर पर लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। सबलोग अपने-अपने ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबलोगों को मालूम है कि हमलोगों ने शुरू से ही कोई जांच की व्यवस्था प्रारंभ में नहीं की थी। जांच की व्यवस्था जब शुरूआती दौर में लागू हुई, जब लॉकडाउन लागू हुआ तो हमलोगों ने एक मीटिंग में तय किया कि हमलोग एक दिन में एक लाख से ज्यादा कराकर देश में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब ये दौर बढ़ा, लॉकडाउन खत्म हुआ। उसके बाद से देखते हैं कि

जून, जुलाई में किस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा। ये सिर्फ यहां नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये स्थिति बनी हुई है। हमने कहा कि बड़े पैमाने पर इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच करने के लिए जो सिस्टम हमलोगों ने शुरू किया। सरकार के प्रयासों से जांच की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। लोग समझ रहे थे कि जांच 1 लाख प्रतिदिन अधिकतम होगा लेकिन आप जानते हैं कि कल 1 लाख 20 हजार से भी अधिक जांच हुई और ये सिलसिला हमलोग बढ़ाते जा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच हो, सभी इच्छुक लोगों की जांच हो। प्रखंड स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जांच का इंतजाम किया गया है, जो चाहेंगे उनकी भी जांच हमलोग करवा रहे हैं।

इलाज की त्रिस्तरीय व्यवस्था

कोरोना काल में मरीजों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के जो निजी चिकित्सा संस्थान हैं उनको भी ये सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा हमलोगों ने तीन स्तर पर जांच का इंतजाम कर रखा है।

लक्षणों की गंभीरता के अनुसार, संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पीटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था हमने की है। इसके लिए ऑक्सीजनयुक्त बेड, आई0सी0यू0 वेटिंलेटर की व्यवस्था हमलोग लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए अब निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, उनकी भी भागीदारी हुई है। मरीजों एवं स्वास्थ्यकर्मियों हेतु जितने भी आवश्यक उपकरण और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। होम आइसोलेशन में जिन्हें रहने का सुझाव दिया जाता है उनकी भी जानकारी ली जाती है, मेडिकल किट दिए जाते हैं। दवाएं, मास्क एवं चिकित्सकीय सलाह हेतु पम्पलेट हैं, डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिशिन की सुविधा दी गई है। कॉल सेंटरों के माध्यम से सभी मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है।

लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों छात्रों एवं अन्य लोगों की सहायता

लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिहार के बाहर बहुत लोग फंसे हुए थे। कई मजदूर, छात्र एवं अन्य लोग फंसे हुए थे। उनसे संपर्क करने के लिए भी हमलोगों ने स्थानिक आयुक्त कार्यालय दिल्ली, यहां आपदा प्रबंधन का कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय इन सभी जगहों पर लोगों की बात सुनकर जो भी संभव होता था, किया गया। हमलोगों ने निर्णय लिया कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम 1000 रुपए की सहायता देंगे। अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 21 लाख यानि 20 लाख 95 हजार से भी ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। विशेष ट्रेनों के माध्यम से जब लोगों का बिहार के बाहर से मई महीने में आना शुरू हुआ तो कुछ खास जगहों पर जहां कोरोना का बहुत प्रकोप था, वहां से आने वाले तमाम लोगों को हमलोगों ने यहां बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों पर रखा। 15 लाख से भी ज्यादा लोग क्वारंटाइन केंद्रों में रहे। उन्हें सब तरह की सुविधाएं, रहने का, भोजन का, चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी गई। हमलोगों ने इन केंद्रों पर रहने वाले हरेक व्यक्ति पर 5300 रुपये खर्च किये।

लॉकडाउन के दौरान जरुरतमंदों की सहायता

लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता की गई। लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार की तरफ से 8 हजार 538 करोड़ रुपए खर्च किए गए और राज्य में 1 करोड़ 64 लाख राशन कार्डधारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1000 रुपए प्रति परिवार की दर से 1640 करोड़ रुपए वितरित किये गये। केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है कि नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया जायेगा।

हमलोगों ने तय कर दिया कि राशन कार्ड से जो भी वंचित हैं, किसी ने दरख्वास्त दिया और रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग है उन सबलोगों को राशन कार्ड की सुविधा मिले। इसके बाद शहरी और देहाती इलाके में जीविका समूहों के माध्यम से जो राशन कार्ड से वंचित हैं उन्हें सुविधा मुहैया करायी गई। 23 लाख 38 हजार सुयोग्य परिवारों के लिए राशन कार्ड स्वी.त किए गए। 12 अगस्त 2020 तक 23 लाख 01 हजार लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

असमय वर्षापात से उत्पन्न आपदाजनक स्थिति से निपटने के लिए कार्य

आप देख ही रहे हैं कि मौसम की क्या स्थिति रही है। फरवरी में भी वर्षा, मार्च में भी तीन दिन वर्षा, अप्रैल माह में भी वर्षा से लोग प्रभावित हुए। रबी की फसल प्रभावित हुई तो इसके लिए भी हमलोगों ने काम किया। .षि अनुदान इनपुट के तहत 18 लाख से अधिक किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। लॉकडाउन में विद्यालयों के बंद होने के कारण मैट्रिक एवं इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा में अगली परीक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार शिक्षा दी जा रही है।

अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों के लिए रोजगार सृजन

अन्य राज्यों से जो बिहारी लोग लौटे हैं, जो बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे उनके लिए रोजगार सृजन के लिए भी हमलोगों ने प्रयास शुरू किया है। वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई। इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई। प्रत्येक जिले में उद्योग के 5 छोटे तथा दो बड़े क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हर जिले में 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई है। राज्य में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अगले पांच साल के लिए नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2020 लागू की गई है।

सावधानी ही बचाव: मास्क का उपयोग जरुरी है, सभी रहें सचेत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबलोगों से अनुरोध करते हैं कि लोगों में कोरोना संक्रमण से भय नहीं सजगता होनी चाहिए, लोगों को सचेत होना चाहिए और उसके लिए जो खतरा बढ़ रहा है उससे बचने के लिए अमल करना चाहिए। लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मास्क उपलब्ध कराने के लिए भी हमलोग कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए। हाथ को साबुन से साफ करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं को, जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं पुरुष हों या स्त्री या 10 वर्ष तक के बच्चे और बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इलाज कराना है तो ही बाहर निकलें वरना उनको घर के अंदर रहना चाहिए। चूँकि इनलोगों पर खतरा सबसे ज्यादा है। वैसी स्थिति में इस बात का पूरे तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना से बचाव हेतु सरकार ये प्रयास कर रही है। सभी लोगों को सजग और सचेत रहने के बाद ही कोरोना से मुक्ति पायी जा सकती है। अब ये कोरोना के लिए जो भी संभव है किया ही जा रहा है। बहुत लोग तो बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं। किसको क्या पता है। इस बीमारी का

फैलाव पूरी दुनिया में है, इस बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता था। सभी लोगों को लगता था कि मार्च के अंत में ये ठीक हो जाएगा। 35 डिग्री का टेम्प्रेचर आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। टेम्प्रेचर बढ़ने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ।

असमय वर्षापात से फसल बबार्दी और बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए कार्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक संबोधन में कहा था कि आप पटना का सोच लीजिये। एक से दो दिन ही 40 डिग्री टेम्प्रेचर हुआ और गया में उससे थोड़ा ज्यादा हुआ। गर्मी के दिन में भी पूरी गर्मी नहीं पड़ी और आप देख ही रहे हैं कि रबी की फसल की बबार्दी किस तरह से हुई और आज कल क्या स्थिति बनी हुई है।

इस स्थिति से सभी लोग वाकिफ भी हैं। शुरू से हमलोगों को बताया गया है कि 15 जून से मॉनसून शुरू होता है। इस बार तो 15 जून से पहले ही मॉनसून शुरू हो गया और नेपाल में भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से उत्तर बिहार के 16 जिले प्रभावित हो गए। 14 अगस्त, 2020 के आकड़े के अनुसार 16 जिलों में 130 प्रखंडों के अंतर्गत 1303 पंचायतों में लगभग 81 लाख से भी ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ स्थानों पर जाना संभव नहीं था। एयर ड्रापिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों के बीच फूड पैकेट भी पहुंचाने के लिए काम किया गया है। बाढ़ राहत शिविर चलाये जा रहे हैं, वहां पर लोगों के रहने के लिए इंतजाम किये गये हैं और उसके अलावा सामुदायिक रसोई केंद्र बनाये गए हैं। इनमें किसी दिन 10 लाख के करीब और अब 9 लाख लोगों के लिए भोजन करने का प्रबंध है। आप जान लीजिये हम एक दो जगह जा करके देख भी आए हैं। हमने शुरू से कहा है कि राहत केंद्र में रहने वाले और सामुदायिक रसोई केंद्र जिसमें भोजन का इंतजाम करते हैं, इन दोनों जगहों पर कोरोना की जांच जरूर करवाइये और जॉच करायी भी जा रही है।

कोरोना जांच से फायदा भी हुआ है। एक जगह 30-40 लोगों की जांच में पता चला कि चार लोग पॉजिटिव हैं। अगर जांच नहीं करायी गयी होती तो आप कल्पना कीजिए कि जो लोग भी वहां रहने या भोजन करने के लिए आते तो कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते। हमलोग ज्यादा प्रचारित नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं और ये सब काम यहां पर किया जा रहा है। कल तक का जो फिगर हैं, जितने भी बाढ़ पीड़ित परिवार हैं आप तो जानते ही हैं कि जो भी आपदा पीड़ित लोग हैं सरकार के खजाने पर उनका सबसे पहला अधिकार है।

जब से बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया है, हम 2006-07 से ही ये बातें कह रहे हैं। कहां किस राज्य में मिलता है ये हमको नहीं मालूम, पता करियेगा। यहां पर जो परिवार पीड़ित होते हैं उन सब लोगों को प्रति परिवार जी0आर0 रिलीफ दिया जाता है। वर्ष 2007 में तो हमलोगो ने एक-एक क्विंटल अनाज बांटा था। उसके बाद तो कोशी त्रासदी हुई तब हमलोगों ने ये तय किया कि 6000 हजार रुपये यानि 3000 हजार रुपए अनाज के लिए और बाकी 3000 हजार रुपए कपड़ा और बर्तन के लिए प्रति परिवार हम लोग देते हैं। पिछले वर्ष से तो सीधे उनके एकाउंट में रुपए भेजे जा रहे हैं।

पिछले साल भी ये सुविधा शुरू कर दी गई और इस बार भी हमलोगों ने ये सुविधा शुरू कर दी और 14 अगस्त 2020 तक 7 लाख 79 हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000 हजार रुपये की दर से 467 करोड़ रुपए जी0आर0 अनुग्रह सहायता राशि उनके खाते में पहुँच गई है। जो बाकी बचे प्रभावित परिवार हैं उनके खाते में दस दिनों के अंदर पैसा पहुँच जाएगा। बाढ़ से जहां कहीं भी फसल क्षति हुई है उसका भी आंकलन कराया जा रहा है और उनको भी सहायता दी जायेगी।

इसके अलावा जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको भी सहायता देने के साथ-साथ मृतक पशुओं के लिए भी सहायता दी जायेगी। बाढ़ की स्थिति पर तो नजर रखी जा रही है। जून, जुलाई और अगस्त महीने में वर्षापात की ये स्थिति है। सितम्बर और कभी-कभी अक्टूबर माह में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। हमलोग तो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं और हमलोग का जो भी संकल्प है उसके आधार पर काम करते हैं। जो हमारी अद्यतन समस्या है इसके लिए हमलोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं।

विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द के लिए किया गया कार्य

मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि बिहार के लोगों ने हमलोगों को जिम्मेवारी दी है, उसका ये तीसरा टर्म चल रहा है। हमलोगों ने विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द्र कायम रखने के लिए काम किया है। आप सभी जानते हैं शुरूआती दौर से ही हमलोगों ने तय किया था कि पुलिस थाने में एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें समय लगा और ये पिछले साल से लागू हो गया। हर प्रकार से हमलोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कितना अपराध होता था, अब क्या होता है ? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 में पूरे देश के अपराध के बारे में आंकड़े प्रकाशित हुये। राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के राष्ट्रीय अपराध में संज्ञेय अपराध का औसत दर 01 लाख की जनसंख्या पर 383.05 है। देश के औसत से बिहार का काफी कम 222.01 है। ये जान लीजिए अपराध भी बहुत ज्यादा नियंत्रित हुआ है। कुछ भी आप कर लीजिये लेकिन कुछ आदमी गड़बड़ करेगा, बायें-दायें करेगा। अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। इतना बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी आबादी है तब ये स्थिति है। इसके अलावा साम्प्रदायिक सौहार्द्र और सामाजिक सद्भाव के लिए हर तरह का काम हमलोग करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय हमलोगों ने लिया। कुल लक्षित कब्रिस्तान जिनकी पहचान की गई थी 2006 में 8 हजार 64 है उसके विरुद्ध 6 हजार 299 की घेराबंदी की जा चुकी हैं। क्राइम, करप्शन और कम्यूनिलिज्म के प्रति हमलोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये हमेशा रहेगा। बार बार हम कहते हैं, जब भी हम अपराध का विश्लेषण करते हैं खास करके मर्डर का विश्लेषण करवाते हैं तो 60 प्रतिशत सम्पति और भूमि विवाद का कारण पता चलता है। आप सबको मालूम तो है कि सर्वे सेटलमेंट का काम और एरियल सर्वे भी करवा रहे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए भौतिक सत्यापन के लिए 6,308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि ये काम हो जाए। इसके अलावा पारिवारिक बँटवारे का निबंधन शुल्क 8 प्रतिशत लगता था और उसके चलते रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। इसको देखते हुए हमलोगों ने निबंधन शुल्क सांकेतिक रूप से मात्र 100 रुपये कर दिया। जमीन का बंटवारा हो जाने से विवाद घटेगा। दाखिल खारिज को लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में लाकर इसे अद्यतन करने का अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि यह पेंडिंग न रहे। भूमि विवाद के निपटारे के लिए सभी जगह जो सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी हैं उन्हें हर थाने में प्रत्येक सप्ताह एक मीटिंग कर विवादों का समाधान करना है। इसका अनुश्रवण करने के लिए एस0डी0ओ0 और डी0एस0पी0 को दो सप्ताह (15 दिन) में एक दिन मीटिंग करनी है। इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक माह में एक दिन मीटिंग करेंगे। इस प्रकार हमलोगों ने एक-एक काम करने की कोशिश की है।

प्रशासनिक स्तर पर काफी सुधार हुए

मुख्यमंत्री तर्क देते हुए कहते हैं कि प्रशासनिक सुधार के लिए भी अनेक काम किये गये। ब्लॉक, सब डिविजन और जिला में जाति, आय, आवास जैसे अन्य सर्टिफिकेट के लिए लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था। इसके लिए हमलोगों ने वर्ष 2011 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून शुरू किया। जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा अधिकार कानून का फायदा उठाने वाले 75 प्रतिशत लोग हैं। इसके लिए अलग केंद्र बना दिये गये। लोक सेवा अधिकार कानून के तहत अब तक 23 करोड़ 88 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ है। हमने वर्ष 2016 में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया। इसमें निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायतों का निपटारा तेजी से होता है। अब तक 07 लाख 03 हजार से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून में संशोधन कर हाल ही में राशन कार्ड को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। पहले राशन कार्ड बनाने का काम सिर्फ लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में ही था। अब कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून का फायदा उठा सकता है। इस टेन्योर में हमलोगों ने सरकारी अधिकारी और कर्मियों के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया और वर्ष 2019 में इसे लागू भी कर दिया गया। इसके अंतर्गत अब तक सरकारी सेवकों के 2,227 आवेदनों का निष्पादन हुआ है। यह मार्च के पहले का आंकड़ा है क्योंकि कोरोना के कारण सभी चीजें अव्यवस्थित हो गयीं।

बिहार को विकसित करने के लिए आधारभूत संरचना पर काम हो रहा है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि आधारभूत संरचना के लिए काफी काम किया है। पहले कितनी सड़कें थीं और अब कितनी सड़कें हैं। हमलोगों ने

बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से 06 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। अब 05 घंटे के अंदर पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अनेक सड़कों और पुलों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चैड़ीकरण कराया जा रहा है। हमलोगों ने सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ-साथ उसका अनुरक्षण करने का भी निर्णय लिया है। इसे भी लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में लाया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है कि अब सड़कें सिर्फ बनेंगी ही नहीं बल्कि उसका निरंतर मेंटेनेंस भी होगा। राज्य योजना के अंतर्गत पथों और पुलों के निर्माण को देखें तो वर्ष 2005 के बाद 6,047 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें 18 मेगा पुल शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलियों का निर्माण भी कराया गया है। राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2005 के बाद से अब तक सड़कों के निर्माण पर 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 के बाद ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 34,287 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। हमने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा था कि हमलोग बिजली की स्थिति में सुधार ला रहे हैं और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं आया तो वर्ष 2015 के चुनाव में लोगों के बीच वोट मांगने नहीं जायेंगे। बिजली की स्थिति में काफी सुधार आया और वर्ष 2015 के बाद हमलोगों ने इसे सात निश्चय में शामिल किया। सात निश्चय के अंतर्गत दिसम्बर 2018 तक हर इच्छुक परिवार को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और यह काम अक्टूबर 2018 में ही पूरा हो गया। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी। इसके बाद बिजली के सभी जर्जर तार बदले गये। हमलोगों ने .षि कार्य के लिए अलग .षि फीडर बनाकर हर इच्छुक किसान को बिजली पहुँचाने का काम शुरू किया है। वर्ष 2005 के बाद बिजली के क्षेत्र में 48,678 करोड़ रुपए खर्च किये गये।

समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास

बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है इसलिए समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण स्थलों के उत्खनन का कार्य जारी है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का कहा है कि बिहार म्यूजियम का निर्माण जब हो रहा था तो कुछ लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा। अब बिहार म्यूजियम की कितनी चर्चा हो रही है। पटना म्यूजियम के विस्तारीकरण की भी स्वी.ति दे दी गयी है। उसका भी काम शुरू होने वाला है। वह भी बनेगा तो देखने लायक होगा। मुख्य सचिव को हमने कह दिया है कि मेरी इच्छा है कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ दीजिये ताकि लोग एक-दूसरे का भ्रमण कर सकें। अब यहां साइंस सिटी का भी निर्माण हो रहा है और उसका नामकरण पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। गाँधी मैदान के सामने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में ज्ञान भवन और बापू सभागार का निर्माण कराया गया और इसके पिछले हिस्से में सभ्यता द्वारा बनाया गया। बापू सभागार में 5,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया गया जो 9 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आएगा तो

वह सुरक्षित रहेगा। वहां आपदा प्रबंधन का मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय बनाया गया ताकि वहां से हर परिस्थिति में लोगों को राहत देने का काम किया जा सके। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य जारी है। बोधगया में महाबोधि सांस्.तिक केंद्र बोधगया का निर्माण कार्य जारी है।

शिक्षा - समग्र मानव विकास पर विशेष ध्यान

शिक्षा सबके लिए जरुरी और इसे सार्थक कर दिखाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और कथनी से ज्यादा करनी पर यकीन करने वाले भी है। तभी तो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लडकियों के लिए हमलोगों ने कई योजनायें शुरू कीं, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि वर्ष 2019 की मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में लड़कों से अधिक लड़कियों की संख्या थी। बिहार का प्रजनन दर तो बहुत ज्यादा है और आबादी का घनत्व अधिक है। वर्ष 2011 के आकंड़ों के मुताबिक देश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में करीब 380 है और बिहार में 1,100 से भी ज्यादा है। बिहार के लोगों ने जब हमें काम करने का मौका दिया तो प्रजनन दर 4.3 था जो अब घटकर 3.2 हो गया है। हम बराबर इस बात की चर्चा करते हैं कि जब हमलोगों ने आकलन किया कि अगर पति-पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर 02 है और बिहार का भी औसत प्रजनन दर 02 है। यदि पत्नी इंटर पास है तो देश का औसत प्रजनन दर 1.7 है और बिहार का औसत प्रजनन दर 1.6 है। इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया और पिछले साल ही आकलन में हमने देखा कि 5,081 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया है। शेष 3,305 पंचायतों में पूरी मजबूती से काम शुरू किया गया है। इस साल अप्रैल माह से ही सभी पंचायतों में 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू होने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो सकी है। अब जब भी पढ़ाई शुरू होगी हर पंचायत में 9वीं क्लास की पढ़ाई प्रारम्भ हो जाएगी। इससे बिहार की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है उत्तरोतर विकास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमलोगों ने काफी काम किया है। वर्ष 2006 में हमने आकलन कराया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में औसतन 39 व्यक्ति यानि एक दिन में 01 व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। बिहार में नये-नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। हमने बिहार में पोलियो का उन्मूलन किया। पल्स पोलियो अभियान के बाद एक भी पोलियो का मामला दर्ज नहीं हुआ है। पहले बिहार में नियमित टीकाकरण मात्र 18 प्रतिशत था। हमने इसको बढ़ाया और हमने अब तय कर दिया कि देश के टॉप 5 राज्यों में से एक हमारा बिहार रहेगा। बिहार में अब टीकाकरण 86 प्रतिशत हो चुका है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

कृषि पर पूरी तरह आधारित है बिहार का विकास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि को लेकर भी काम किया गया है। अभी तीसरे .षि रोड मैप पर काम चल रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ी है। कौन सा काम हमलोग नहीं कर रहे हैं ? मौसम के अनुकूल फसल चक्र के लिए हमने पहले 8 जिलों से काम शुरू किया। इसे अब सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया है। एक-एक काम हमलोग कर रहे हैं। फसल अवशेष को लोग जला देते हैं। इसके खिलाफ हमलोग अभियान चला रहे हैं। फसल अवशेष को लोग नहीं जलायें, इसके लिए हमलोग अनुदान देते हैं। फसल अवशेष जिसको पराली कहते हैं, इसके प्रबंधन के लिए चार .षि यंत्रों पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 75 प्रतिशत का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। कंबाइंड हार्वेस्टर के कारण लोगों ने पराली को जलाना शुरू किया। इससे ही ये समस्या आयी है। बिहार के भी कई जिलों में ये शुरू हो गया है। इससे बचने के लिए हमलोग चार .षि यंत्रों पर अनुदान दे रहे हैं। बुआई के लिए हैप्पी सीडर एवं जीरो टिलेट मशीन, फसल

अवशेष को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिछाने के लिए रोटरी कल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर एवं स्ट्रॉ बेलर, फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र पर हमलोग अनुदान दे रहे हैं। बिहार में फसल बीमा योजना को समाप्त करके बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की गयी है। मछली का उत्पादन 2007-08 में 2 लाख 61 हजार मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर 6 लाख 41 हजार मीट्रिक टन हो गया है। बिहार इनलैंड मछली उत्पादन में चैथे स्थान पर पहुंच गया है। अब राज्य में चावल, गेहूं और मक्के की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई है। हमें आगे अगर मौका मिलेगा तो किसानों के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। इसको लेकर सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है।

न्याय के साथ विकास हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान

न्याय के साथ विकास हमारा लक्ष्य है। हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान हमारा लक्ष्य है। जो हाशिये पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में 5 वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दे रहे हैं। सभी पंचायतों में 3 अनुसूचित जाति जनजाति और 2 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब तक 41,930 आवेदनों के विरुद्ध 27,005 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला है।

स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल बनाए रखने हेतु कार्य योजना

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। एक महीने के समतुल्य वेतन, प्रोत्साहन राशि के रुप में उनको देने का निर्णय लिया गया है। कर्तव्य के दौरान अगर किसी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में उनके आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तो होगी ही और संबंधित कर्मी के रिटायरमेंट तिथि तक वेतन के बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भी सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा की सुविधा दी गई है।

नीतीश के सात निश्चय पार्ट -2 का सच और राजनीतिक संदेश क्या है?

बिहार में चुनाव घोषणा के साथ साथ एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और जनता दल युनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष , नीतीश कुमार ने अपना सात निश्चय पार्ट -2 सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रख दिया हैं. बिहार में चुनाव घोषणा के साथ साथ एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और जनता दल युनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष , नीतीश कुमार ने अपना सात निश्चय पार्ट -2 सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रख दिया हैं. भले ये उनका घोषणा पत्र हो लेकिन राज्य की राजनीति में ये पहली बार हुआ है कि घोषणा के दिन घोषणा पत्र को जारी कर दिया जाए. निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस कदम से उनके सहयोगी और विपक्ष के लोग अचरज में हैं. लेकिन इस कदम से कई बातें सामने आयी. पहला नीतीश इस बार के विधानसभा चुनाव की अधिकांश तैयारी पहले से करके बैठे हैं और उन्होंने भविष्य में क्या करना हैं उसके बारे में फिलहाल सहयोगियों से पूछने के बजाय खुद से समस्या और उसका निराकरण कैसे होगा उसका हल ढूंढा है ? जैसे नगर विकास विभाग जो हमेशा से भाजपा के पास रहा है उसके बावजूद नीतीश कुमार की हर बारिश में फजीहत होती है. इसी से सीख कर शहरों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज की बात उन्होंने की है. कुछ निश्चय जैसे हर खेत तक पानी को उन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से घोषति कर दिया था. इसलिए वो बातें पुरानी हो गयी थीं. वैसे ही महिलाओं के प्रति नीतीश ने और उदारता दिखाई है. जिसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से इस बार भी मतदान में मिलेगा. हालांकि भाजपा के लिए उन्होंने अपने निश्चय में काम करने की पूरी गुंजाइश छोड़ी है. जैसे उन्होंने ये बात मानते हुए कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती. इस सच को स्वीकार करते हुए स्किल प्रशिक्षण पर कई घोषणा तो की लेकिन उन्होंने एक स्किल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा नहीं की क्योंकि ये पाँच वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज में इसकी घोषणा तो कर दी गयी लेकिन उसका क्रियान्वयन करना भूल गये.इसलिए भाजपा को इसकी स्थापना का श्रेय लेने का नीतीश कुमार ने स्कोप छोड़ा हुआ है. वैसे ही एक लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था. वैसे ही डिजिटल बिहार के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क ,ग्रामीण इलाकों में बीपीओ और एक हजार मोबाइल टावर लगाने की पैकेज में घोषणा की गई थी. लेकिन इसे आज तक भाजपा पूरा नहीं कर पायी. यही कारण है कि प्रधानमंत्री के इस पैकेज पर कितना काम हुआ उसकी चर्चा भाजपा के नेता दिल्ली से पटना तक नहीं करते. लेकिन सबसे अधिक नीतीश ने इस निश्चय को सार्वजनिक कर नाम के सहयोगी और सबसे मुखर आलोचक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को संदेश दिया है कि शासन का मुखिया जब तक जनता की कृपा हैं मैं हूं. लेकिन आप सहयोगी होने के नाते मुझे टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते. चिराग हमेशा इस बात को कहते हैं कि सात निश्चय महागठबंधन का कार्यक्रम हैं और जब तक एनडीए का साझा घोषणा पत्र नहीं बनता उन्हें सरकार से विरोध होगा. नीतीश ने एक तरह से उन्हें साफ दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया है कि भले भाजपा आपकी सीटों के समझौते पर मांग मान ले लेकिन सरकार और मेरी आलोचना कर आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिए.

देश के आर्थिक विकास को लग सकते हैं पंख

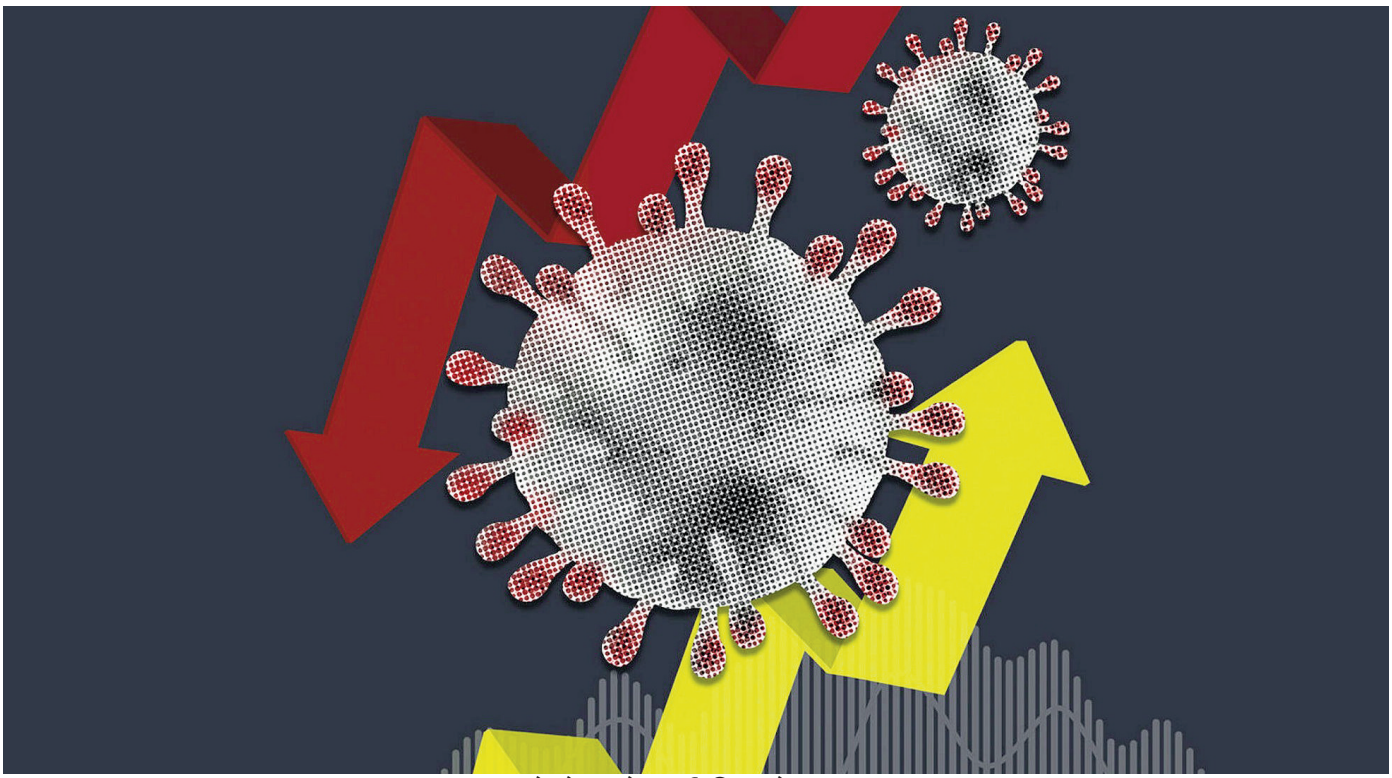

किसी भी संस्थान की सफलता में उसके मजदूरों एवं कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना मजदूरों एवं कर्मचारियों के सहयोग के कोई भी संस्थान सफलता पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए संस्थानों में कार्य कर रहे मजदूरों एवं कर्मचारियों को ह्लमजदूर/कर्मचारी शक्तिह्व की संज्ञा दी गई है। हमारे देश में दुर्भाग्य से मजदूरों एवं कर्मचारियों के शोषण की कई घटनाएँ सामने आती रही हैं। यथा, मजदूरों एवं कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं करना एवं उनसे निर्धारित समय सीमा से अधिक कार्य लेना एवं आदि, प्रमुख रूप से शामिल हैं।

हमारे देश में कई विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि देश में रोजगार की समस्या तो कम है परंतु कम मजदूरी की समस्या अत्यधिक है। समाज में पढ़े लिखे डिग्रीधारी वर्ग को कम वेतन/मजदूरी वाले रोजगार तो मिल जाते हैं परंतु उसके द्वारा की गई पढ़ाई के अनुसार अच्छे वेतन/मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसकी तुलना में जब हम अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों की और देखते हैं तो वहाँ लगभग प्रत्येक कर्मचारी खुश नजर आता है एवं उसकी अपने संस्थान के प्रति वफादारी एवं उत्पादकता भारत की तुलना में बहुत अधिक पायी जाती है। इसका मुख्य कारण है वहाँ पर प्रत्येक मजदूर एवं कर्मचारी को पूर्व निर्धारित दर से न्यूनतम मजदूरी एवं वेतन का समय पर भुगतान करना है। इन देशों में न्यूनतम मजदूरी एवं वेतन की दरें भी वहाँ के जीवन स्तर इंडेक्स को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है। विकसित देशों में तो न्यूनतम मजदूरी एवं वेतन की दर प्रति घंटा तय की जाती है एवं इसके समय पर भुगतान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में सामान्यतः 10 से 20 अमेरिकी डॉलर के बीच में प्रति घंटा मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन में 8 घंटे कार्य करे तो पूरे माह में वह व्यक्ति 1600 से 3200 अमेरिकी डॉलर (10/20७8७20) आसानी से कमा लेता है। जबकि यहाँ के जीवन स्तर इंडेक्स के अनुसार लगभग 1200 से 1500 अमेरिकी डॉलर कमाने वाला व्यक्ति आसानी से अपना गुजर बसर कर सकता है। इन देशों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों का पालन कड़ाई से किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मजदूरों एवं कर्मचारियों में असंतोष की भावना नहीं के बराबर देखने को मिलती है। बल्कि, अमूमन यहाँ पर चूँकि मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग प्रसन्न रहता है अतः उनकी उत्पादकता भी तुलनात्मक रूप से अधिक पायी जाती है।

हमारे देश में कई विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि देश में रोजगार की समस्या तो कम है परंतु कम मजदूरी की समस्या अत्यधिक है। समाज में पढ़े लिखे डिग्रीधारी वर्ग को कम वेतन/मजदूरी वाले रोजगार तो मिल जाते हैं परंतु उसके द्वारा की गई पढ़ाई के अनुसार अच्छे वेतन/मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसकी तुलना में जब हम अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों की और देखते हैं तो वहाँ लगभग प्रत्येक कर्मचारी खुश नजर आता है एवं उसकी अपने संस्थान के प्रति वफादारी एवं उत्पादकता भारत की तुलना में बहुत अधिक पायी जाती है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम

प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान कुछ महीनों पहले ही शुरू किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक ग्रामीण महिला रेणुका ढीमर ने इसकी शुरूआत आज से चार साल पहले ही कर दी थी। खेती और मजदूरी करके गुजर-बसर करने वाले परिवार की इस बहू ने 2016 में प्रशासन से मिले 25-30 कड़कनाथ के चूजों को पालना शुरू किया, जो समय के साथ बढ़ते चले गए और आज यही रेणुका और उनके परिवार की आय का मुख्य साधन बन गया है। मुगीर्पालन से ही रेणुका की आय हर महीने 15 हजार हो रही है। उनके इस प्रयास की सराहना न केवल गांव के लोग कर रहे हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी समय-समय पर उनके घर पहुंचकर उत्साह बढ़ाते हैं।

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम सुरगी। मुख्यतः खेती-किसानी और मजदूरी पर आश्रित लगभग 3,500 जनसंख्या वाले इस गांव में चार साल पहले प्रशासन की तरफ से 70-80 परिवारों को कड़कनाथ मुगीर्पालन हेतू चूजों का वितरण किया गया था। कुछ महीनों तक पालने के बाद ग्रामीण इस व्यवसाय को छोड़कर वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लग गए। लेकिन कक्षा दसवीं तक शिक्षित रेणुका ढीमर एकमात्र थीं जिसने उन चूजों को पालना शुरू किया और उसे रोजगार के रूप में बढ़ाया। रेणुका के साथ इस कार्य को बडे.स्तर पर करने के लिए गांव की 10 महिलाओं ने सरस्वती स्व-सहायता समूह बनाया। हालांकि कुछ समय तक साथ काम करने के बाद सभी महिलाओं ने साथ छोड़ दिया और रेणुका अकेले ही कड़कनाथ मुगीर्पालन और बिक्री का कार्य करने लगीं।

कड़कनाथ मुगीर्पालन का व्यवसाय बढ़ता देख कृषि विज्ञान केन्द्र, राजनांदगांव ने भी 2017 में रेणुका को बिहान योजना के अंतर्गत हेचरी मशीन उपलब्ध कराया तथा उसे चलाने के लिए टेक्निकल विभाग द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई। इस मशीन से एक बार में 600 अंडे से चूजे निकाले जा सकते हैं जिनकी प्रोसेसिंग में 21 दिन का समय लगता है। हेचरी का फायदा यह है कि कड़कनाथ के अंडे यहां गर्माहट में सिंकते हैं और जल्द चूजे के रूप में विकसित हो जाते हैं। घर के एक कमरे में 25-30 चूजों के साथ शुरू किया गया यह व्यवसाय वर्तमान में व्यापक रूप ले चुका है। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत मुगीर्पालन शेड भी बना दिया जिसके बाद से अब रेणुका अपने घर पर एक साथ लगभग 1000 मुर्गियों को रख सकती हैं। एक कड़कनाथ मुर्गी या मुर्गे का वजन लगभग 1 से 2 किलो तक होता है। वहीं वनराज कड़कनाथ मुर्गी का वजन ढाई किलो से चार किलो तक होता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही जगहों पर कड़कनाथ की जबरदस्त डिमांड है। यही कारण है कि कड़कनाथ प्रति किलों बाजार में 500 रूपए तक बिकता है।

कड़कनाथ कुक्कुट पालन से रेणुका के जीवन में परिवर्तन आया है। चार साल पहले की अपनी स्थिति को याद करते हुए वो बताती हैं कि पहले मैं और मेरे

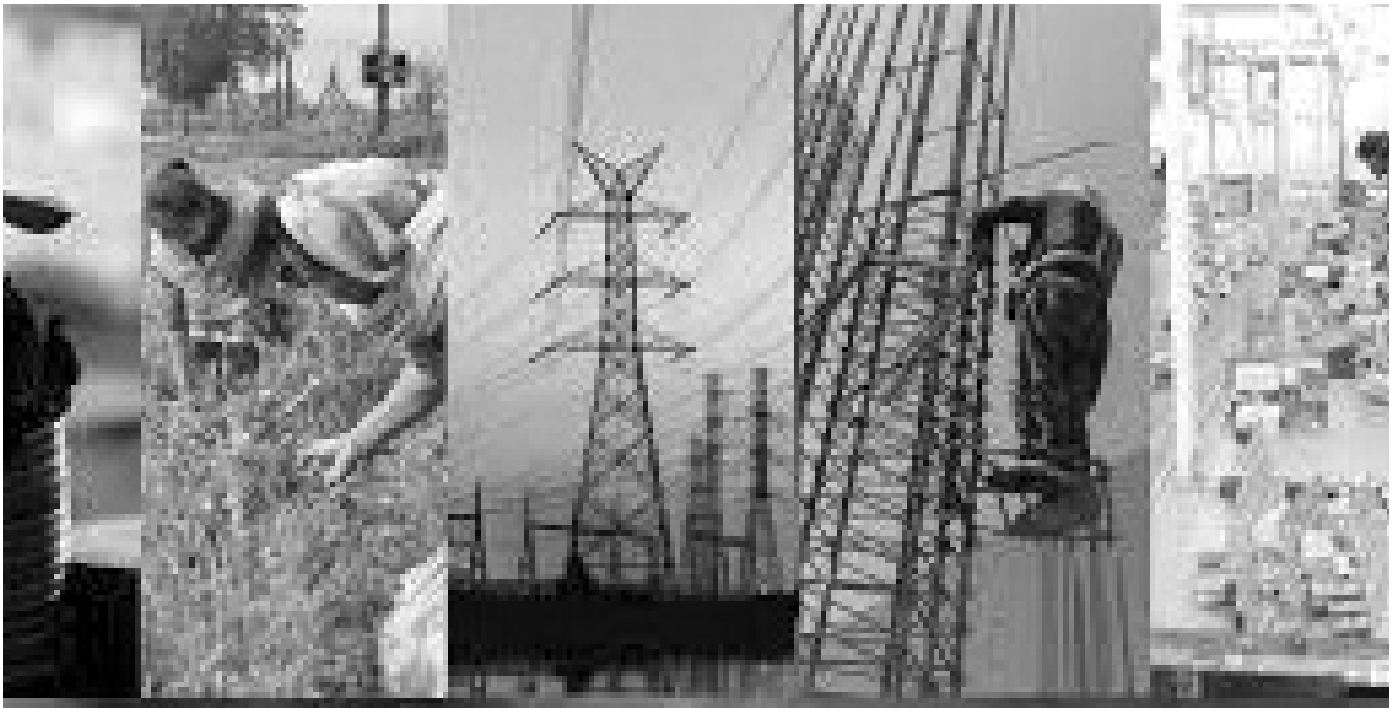

पति राधेश्याम ढीमर दोनों मजदूरी करने जाया करते थे, कभी काम मिलता, तो कभी नहीं मिलता था। काम मिल भी जाता तो 150 से 200 रूपए तक ही एक दिन की कमाई होती थी। मुश्किल से घर में खाने का सामान ला पाते थे, ऐसे में बच्चों की शिक्षा एवं परिवार की अन्य जरूरतों को लेकर हमेशा मन में चिंता बनी रहती थी। अपनी मेहनत और सरकार के सहयोग को धन्यवाद देती हुई रेणुका कहती हैं कि कड़कनाथ पालन से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, अब अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने में कामयाब हुई हैं। रेणुका अब कड़कनाथ के बडे. मुर्गे और मुर्गियों के साथ चूजों को भी बेचने का व्यवसाय करती हैं।

जिसके लिए वह एडवांस में ऑर्डर लेती हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 10-12 जिले से व्यापारी उनसे कड़कनाथ मुर्गी खरीदने आते हैं तथा जिला मुख्यालय राजनांदगांव से रोज 4 से 5 किसान मुर्गी पालन की जानकारी लेने भी आते हैं। जिन्हें रेणुका निःशुल्क जानकारी देती हैं। सभी स्तर पर कड़कनाथ की डिमांड होने के कारण इस व्यवसाय से रेणुका ढीमर को फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 30,000 हजार के करीब कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री करती हैं। जिसमें से 15 हजार उनकी देखरेख, दाना खिलाने एवं टीका लगाने जैसे कार्यों में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार हर महीने उन्हें लगभग 15 हजार रूपए की कमाई होती है।

कुक्कुट पालन में रेणुका की सफलता को दिखाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी समय-समय पर राज्य एवं राज्य के बाहर होने वाले कृषि संबंधी आयोजनों में प्रदर्शनी लगाया जाता है। ताकि सभी किसान इस व्यवसाय के बारे में जानकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सकें। रेणुका ने बताया कि वह अपने व्यवसाय से संबंधित जानकारी देने के लिए दिल्ली भी जा चुकीं हैं जहां आयोजित प्रदर्शनी में कड़कनाथ पालन से संबंधित स्टॉल लगाकर जानकारी दी गई थी।

कड़कनाथ कुक्कुट पालन से रेणुका के जीवन में परिवर्तन आया है। चार साल पहले की अपनी स्थिति को याद करते हुए वो बताती हैं कि पहले मैं और मेरे पति राधेश्याम ढीमर दोनों मजदूरी करने जाया करते थे, कभी काम मिलता, तो कभी नहीं मिलता था। काम मिल भी जाता तो 150 से 200 रूपए तक ही एक दिन की कमाई होती थी। मुश्किल से घर में खाने का सामान ला पाते थे, ऐसे में बच्चों की शिक्षा एवं परिवार की अन्य जरूरतों को लेकर हमेशा मन में चिंता बनी रहती थी।

एक महीने पहले जिला के कलेक्टर ने भी स्वयं उनके घर पहुंचकर कड़कनाथ मुर्गी पालन व हेचरी की जानकारी ली। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि खेती किसानी के साथ मुगीपालन को भी अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। राजनांदगांव कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ बी.एस. राजपूत बताते हैं कि कड़कनाथ मुर्गे और मुर्गियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है तथा इसमें वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है। यही कारण है कि हृदय रोगियों के लिए भी यह लाभप्रद होता है।

कड़कनाथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य पक्षियों के तुलना में अत्यधिक होता है जिसके कारण इसका सेवन करने से व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलता है। यह विशुद्ध देशी ब्रीड है जो छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के झाबुआ से लाया गया है। कड़कनाथ के विशिष्ट गुणों के कारण बाजार में इसकी काफी मांग है और इसकी कीमत अन्य मुर्गियों की अपेक्षा काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि कड़कनाथ का पालन रेणुका ढीमर की तरह ही राजनांदगांव जिले में 32 ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। जिन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा आजीविका परियोजना के तहत हेचरी मशीन के साथ तकनीकी जानकारियां भी समय-समय पर दी जाती हैं।

कड़कनाथ मुगीपालन का व्यवसाय काफी सरल है इसमें मुर्गियों को कम देखभाल और ज्यादा वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर तकनीकी कौशल के कार्य भी अब सफलतापूर्वक कर रही हैं। इसका एक उदाहरण रेणुका ढीमर हैं। इसी तरह सरकार के सहयोग से राज्य के विभिन्न जिलों कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, रायपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव एवं गरियाबंद में भी अलग-अलग स्तर पर कड़कनाथ पालन का कार्य किया जा रहा है। वास्तव में यह किसानों के लिए खेती किसानी के साथ-साथ सफल उद्यमी बनकर आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने का सबसे अच्छा माध्यम है।

वायुशक्ति की क्षमता को मिली बेमिसाल मजबूती

पिछले दिनों फ्रांस से भारत आए पांचों राफेल आखिरकार 10 सितम्बर को औपचारिक रूप से वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन ऐरो में शामिल होकर भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा बन गए हैं और अब किसी भी मोर्चे पर तैनात होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस समय भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद में उलझा है और ऐसे में दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों राफेल के वायुसेना में शामिल होने से भारत की वायुशक्ति की क्षमता को बेमिसाल मजबूती मिली है। फ्लाईपास्ट के दौरान भारतीय वायुसेना के बाहुबली राफेल ने दुश्मनों को अपनी ताकत का अहसास कराते हुए दिखाया कि वह न केवल तेज गति से उड़ान भरकर दुश्मनों पर टूट सकता है बल्कि कम स्पीड में भी उड़ान भर सकता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के अनुसार राफेल ने वायुसेना को हमारे विरोधियों पर जबरदस्त बढ़त दी है। अम्बाला एयरबेस पर राफेल के राजतिलक समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांसीसी रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले, सीडीएस बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सहित कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर राफेल की विशेषताओं के बारे में फ्रांसीसी रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले का कहना था कि राफेल को हवा का झोंका कह सकते हैं लेकिन युद्ध के मैदान में इसका मतलब आग बरसाने वाला है। समारोह में राजनाथ सिंह ने चीन से तनाव के दौर में चेतावनी भरे दो टूक शब्दों में कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना पूरी दुनिया को एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए, जो हमारी सम्प्रभुता पर नजर रखते हैं।

उनके मुताबिक चीन से तनाव को देखते हुए राफेल लड़ाकू विमानों को सूचना मिलने पर बेहद कम समय में ही वहां तैनात किया जा सकता है। रक्षामंत्री के अनुसार भारत की जिम्मेदारी उसकी क्षेत्रीय सीमा तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये दोनों क्षेत्र वही हैं, जहां चीन अपनी सैन्य आक्रामकता बढ़ा रहा है। राफेल को भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की अद्भुत ताकत रखने वाला लड़ाकू विमान है। दरअसल रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी दक्षता और बेजोड़ इलैक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली वाले विमान किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं हैं। राफेल चीन के बहुचर्चित लड़ाकू विमान जे-20 से भी कई कदम आगे है। पाकिस्तान का एफ-16 भी राफेल के सामने कहीं नहीं ठहरता। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इनकी तुलना राफेल से नहीं की जा सकती क्योंकि राफेल विमान इन लड़ाकू विमानों की तुलना में ज्यादा दक्ष हैं। चीनी जे-20 का मुख्य कार्य स्टील्थ

अम्बाला एयरबेस पर राफेल के राजतिलक समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांसीसी रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले, सीडीएस बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सहित कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर राफेल की विशेषताओं के बारे में फ्रांसीसी रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले का कहना था कि राफेल को 'हवा का झोंका' कह सकते हैं लेकिन युद्ध के मैदान में इसका मतलब आग बरसाने वाला है।

फाइटर का है जबकि राफेल को कई कार्यों में लगाया जा सकता है। हैमर मिसाइलों से लैस राफेल ओमनी-रोल विमान है अर्थात यह एक बार में कम से कम चार मिशन कर सकता है। जे-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

करीब 35 हजार वजनी जे-20 की लंबाई 20.5 मीटर, ऊंचाई 4.45 मीटर और विंगस्पैन 12.88-13.50 मीटर के बीच है अर्थात यह राफेल से बड़ा और भारी है। राफेल की लम्बाई 15.3 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है जबकि इसके विंग्स की लम्बाई 10.9 मीटर है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास मौजूद जेएफ-17 में चीन ने पीएफ-15 मिसाइलें जोड़ी हैं लेकिन फिर भी यह राफेल के मुकाबले में कमजोर है। राफेल का सबसे खतरनाक हथियार है स्कैल्प पीएल-15 एमराम मिसाइल, जो 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान के एफ-16 में एमराम मिसाइलें लगी हैं लेकिन वे केवल 100 किलोमीटर तक ही हमला कर सकती हैं।

भारतीय वायुसेना के पास मिराज-2000, सुखोई-30 एमकेआई जैसे आधुनिक विमान भी हैं लेकिन वे तीसरी या चौथी पीढ़ी के विमान हैं जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसमें आधुनिक हथियारों के प्रयोग के साथ बेहतर सेंसर की भी अत्याधुनिक सुविधा है। वर्ष 2016 में भारत-फ्रांस के बीच 36 राफेल की खरीद के लिए 59 हजार करोड़ रुपये का सौदा हुआ था, जिनमें से 5 राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंच गए थे जबकि चार राफेल की अगली खेप के अगले माह आने की संभावना है। सौदे के मुताबिक 2022 तक भारत को सभी 36 राफेल मिल जाएंगे, जिनमें से पहले 18 राफेल अम्बाला एयरबेस में जबकि शेष 18 पूर्वोत्तर के हाशिमारा एयरबेस में तैनात किए जाएंगे। हालांकि पड़ोसी देशों की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अभी वायुसेना को अभी ऐसे ही और राफेल विमानों की जरूरत है। सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल अरूप साहा कहते हैं कि राफेल हवाई क्षेत्र में शक्ति के मामले में वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने जा रहा है लेकिन देश को कम से कम 126 राफेल विमानों की जरूरत है, जिनकी कल्पना पहले की गई थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख फली होमी मेजर का भी मानना है कि 36 राफेल विमान भारत की हवाई ताकत को तो बढ़ाएंगे लेकिन कम से कम दो और स्क्वाड्रन होने से देश की वायु प्रभुत्व क्षमता काफी मजबूत होगी।

महिलाओं के साथ भेदभाव करता है समाज

भारत में हिंसा के सबसे अधिक केस महिलाओं से ही जुड़े होते हैं। जिनका रूप कुछ भी हो सकता है। हालांकि पुरूष प्रधान इस देश में हमेशा महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंका जाता है। उसे कमजोर, असहाय और अबला समझ कर उसके साथ कभी दोयम दर्जे का तो कभी जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। पुरुषवादी समाज उसे बेटी के रूप में पैतृक संपत्ति से भी वंचित रखना चाहता है। जबकि परिवार में बेटी एक दायित्व के रूप में होती है। इसके बावजूद घर के लड़कों से उसे कमतर समझा जाता है। उसका मुकाम पुरूषों से नीचे और अधीनस्थ ही माना जाता है। इसीलिए लड़कियों को शिक्षा के साथ उसके निर्णय क्षमता का समाज में कोई स्थान नहीं था। उसका सम्मान किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। सवाल यह उठता है कि महिलाओं के प्रति समाज की सोच नकारात्मक क्यों है? कचरे के ढ़ेर में फेंके जाने वाले नवजातों में 97 प्रतिशत लड़कियां ही क्यों होती हैं?

भारत में जन्म से ही महिला हिंसा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। शहर हो या गांव, शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित, उच्च वर्ग हो या निम्न आर्थिक वर्ग, पैसे वाले हों अथवा दो वक्त की रोटी का मुश्किल से जुगाड़ करने वाला परिवार, संगठित हो या असंगठित क्षेत्र सभी जगह महिला हिंसा की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप देखने को मिल जाता है। सभ्य और विकसित समाज में जहाँ आज महिलाएं अपने अस्तित्व की जंग लड़ने में सक्षम हो रही हैं, वहीं इस समाज में उन पर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक हिंसा के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतिदिन देखने या सुनने को मिल ही जाते हैं। सच तो यह है कि यदि महिला अपराधों की जानकारी अखबारों में छपनी बंद हो जाये तो देश के सभी प्रमुख अखबार 3-4 पन्नों में ही सिमट कर रह जायेंगे। नारी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित राज्यों की श्रेणी में है जबकि उत्तराखण्ड उन चंद राज्यों में एक है, जिसे महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित राज्य माना जाता है। हालांकि सत्य का एक दूसरा पहलू यह भी है कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड काफी पीछे है जबकि इस श्रेणी में दिल्ली काफी आगे है। रोजगार देने के मामले में दिल्ली में जहां महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं देखा जाता है वहीं उत्तराखंड में यह प्रवृति काफी प्रभावी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिर्पोट के अनुसार 29 राज्यों की सूची में महिला सुरक्षा में उत्तराखण्ड देश में 13वें पायदान पर है, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ के मुद्दे पर देश भर में यह 10वें पायदान पर है। इस आधार पर यदि हम आंकलन करें तो स्पष्ट है कि भले ही उत्तराखंड में महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है, लेकिन समाज में उसके शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की जाती है और उसकी देखभाल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में यदि उत्तराखंड समाज की महिलाएं पहल करें तो समाज में उन्हें बराबरी का हक मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत मातृ मृत्यु दर में दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। जो इस बात को दशार्ता है कि आज भी भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार के भीतर पोषण संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गर्भ धारण से लेकर प्रसव

के अंतिम अवस्था तक उसे घर के सारे काम करने होते हैं जबकि इस तुलना में उसे बहुत कम पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। जिससे न केवल उसके अंदर खून की कमी होती है बल्कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा बना रहता है। गर्भावस्था में एक महिला को सबसे अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अफसोस कि बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं बेटी के जन्म का सोच सोच कर तनाव में रहती है क्योंकि जो महिलाएं अधिक से अधिक बेटे को जन्म देती हैं उन्हें बेटी जन्म देने वाली माताओं से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। जो हमारे समाज में बेटे और बेटी के प्रति संकीर्ण मानसिकता को दशार्ता है।

महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ज्यादातर कम साक्षरता दर वाले राज्यों में अधिक देखने को मिलते हैं। जिन राज्यों में साक्षरता दर अधिक है वहां भेदभाव और हिंसा के मामले कम दर्ज हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण केरल और लक्षद्वीप है जहां महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में महिला शिक्षा के लिए मुख्य बाधा स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी का होना है। देश के कई छोटे शहरों में माहवारी के समय लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं। धीरे धीरे यही प्रवृति उसे स्कूल से दूर करती चली जाती है। हालांकि इस संबंध में कई राज्य सरकारों द्वारा सकारात्मक कदम उठाते हुए स्कूलों में सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है, जो लड़कियों के ड्राप आउट के आंकड़ा को कम करने में कारगर सिद्ध हो रहा है।

उत्तराखण्ड शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही 10वें पायदान पर क्यों न हो, लेकिन आज भी पर्वतीय महिलाएं सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं। कई महिलाएं जानकारियां होने के बावजूद लाभ पाने की प्रक्रिया से अभिनज्ञ होने के कारण इससे वंचित रह जाती हैं। वहीं शिक्षा प्राप्त करने के मामले में लड़कियाँ इंटर तक ही पहुँच पाती हैं। इसके आगे पारिवारिक ज़िम्मेदारी के कारण उन्हें उच्च शिक्षा छोड़नी पड़ती है। इंटर के बाद स्नातक और उससे आगे की शिक्षा तक बहुत कम लड़कियों को अवसर प्राप्त हो पाता है। ज्यादातर लड़कियों को शादी के बाद अपनी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। हालांकि उन्हें अवसर मिले तो वह भी अपना हुनर और कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं। ऐसी कई लड़कियों की मिसाल है जिन्होंने अवसर मिलने पर सेना, विज्ञान, अर्थशास्त्र, डॉक्टर और संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा पास कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है।

बहरहाल महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के लिए केवल समाज को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। भेदभाव की शुरूआत माँ बाप से बेटा और बेटी के बीच अंतर से शुरू होती है। बेटी को कमजोर ठहरा कर उसे चहारदीवारी में कैद करने और बेटे को मनमजी की आजादी देने से होती है। जिसे समाप्त करना स्वयं मां बाप की ज़िम्मेदारी है। भला यह कैसे संभव है कि बेटा अभिमान और बेटी बोझ बन जाये? जरूरत है इस संकीर्ण सोच को बदलने की। जरूरत है बेटा की तरह ही बेटी को भी सभी अवसर उपलब्ध करवाने की। उसे भी खुले आसमान में उड़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर देने की। वक्त आ गया है कि अब महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाये।

भारत में जन्म से ही महिला हिंसा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। शहर हो या गांव, शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित, उच्च वर्ग हो या निम्न आर्थिक वर्ग, पैसे वाले हों अथवा दो वक्त की रोटी का मुश्किल से जुगाड़ करने वाला परिवार, संगठित हो या असंगठित क्षेत्र सभी जगह महिला हिंसा की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप देखने को मिल जाता है। सभ्य और विकसित समाज में जहाँ आज महिलाएं अपने अस्तित्व की जंग लड़ने में सक्षम हो रही हैं, वहीं इस समाज में उन पर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक हिंसा के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतिदिन देखने या सुनने को मिल ही जाते हैं। सच तो यह है कि यदि महिला अपराधों की जानकारी अखबारों में छपनी बंद हो जाये तो देश के सभी प्रमुख अखबार 3-4 पन्नों में ही सिमट कर रह जायेंगे। नारी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित राज्यों की श्रेणी में है जबकि उत्तराखण्ड उन चंद राज्यों में एक है।

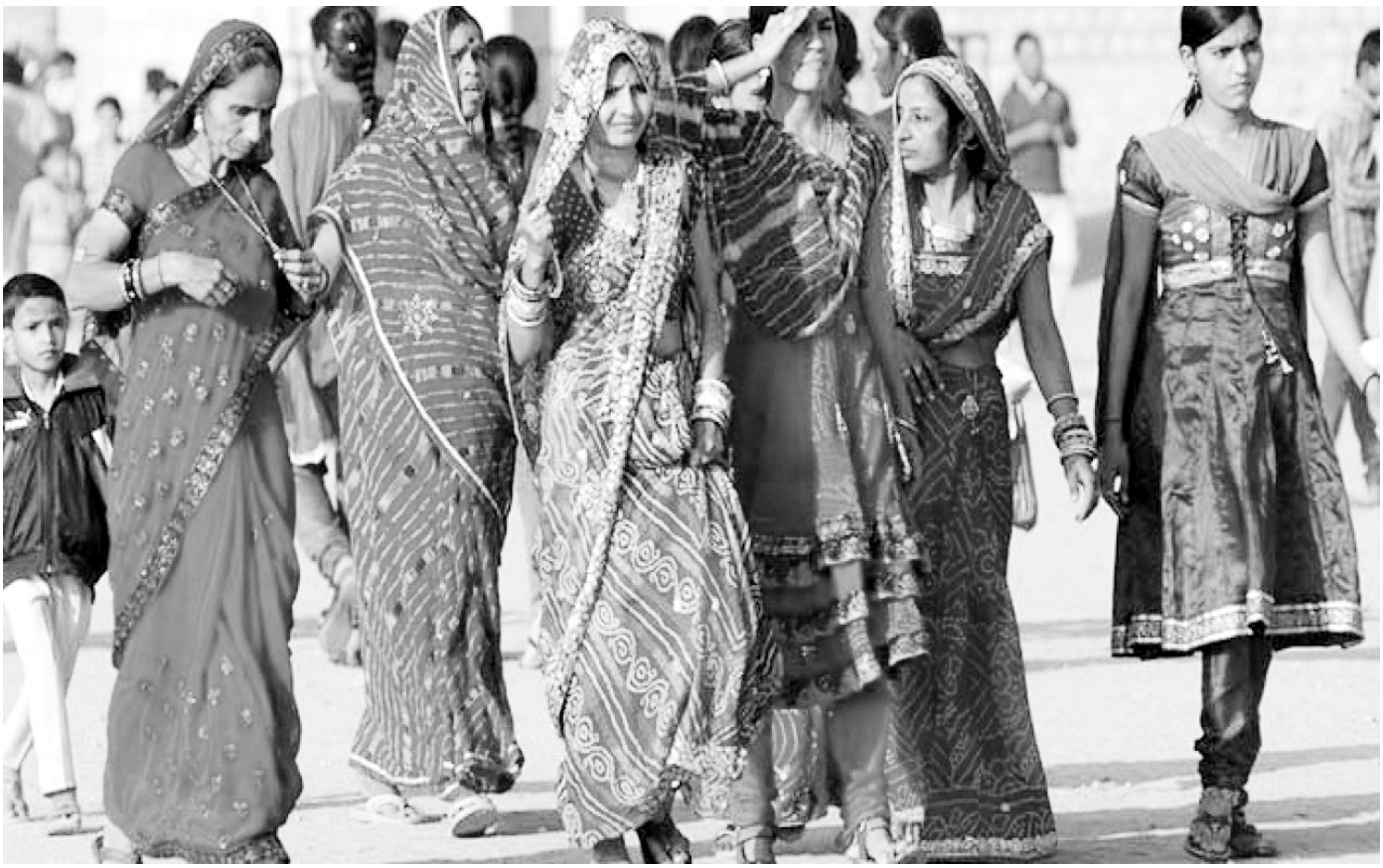

कृषि विधेयक पर देश भर में बवाल

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.

पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी.

प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई हैं. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है. ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं,कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है.अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.

माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी.

क्यों हो रहा है विरोध?

किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा. कृषि मामलों के जानकारों के मुताबिक किसानों की चिंता जायज है. किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफसीआई उसे खरीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में, केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी. प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5: के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है.इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी. प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को

अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, वो करीब 20 लाख किसानों- खासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हजार बताई जाती है, उनके लिए और करीब तीन लाख मंडी मजदूरों के साथ-साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.

किसान नहीं बाजार के लिए विधेयक

दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, 86 प्रतिशत छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं

बिल के मुताबिक इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर्स से फायदा मिलेगा

इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा

आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, हमने जमाखोरी को वैधता दे दी है, इन चीजों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.

विपक्ष का विरोध

विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन श्कालेश अध्यादेश किसान-खेतिहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो

वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है भारत में, यह जरूरी है कि साइबर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और साइबर-फिजिकल सिस्टम और प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योर हों। इसके लिए लोगों, नीतियों और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है।

उन्हें एमएसपी व हक मिलें और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.

हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा

विधेयक को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया था.केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, ष्मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि श्पंजाब और हरियाणा के किसान इससे खुश नहीं हैं.

सरकार का क्या है तर्क?

मोदी ने इसे आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने वाला विधेयक बताया.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं.उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहें हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रह हैं. मोदी ने कहा कि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों पर राज करने वालों ने अपने घोषणापत्र में लिखी थी. मोदी ने कहा कि यहां विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है.उन्होंने कहा बिचैलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना जरूरी था.इसके पहले ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, ष्किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता क्यों,अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा. करार अधिनियम से कृषक सशक्त होगा. व समान स्तर पर एमएनसी,बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा तथा सरकार उसके हितों को संरक्षित करेगी। किसानों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे,निश्चित समयावधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा.उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे.

क्या किसानों का हक मार लेंगे बड़े उद्योगपति?

केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे तीन में से दो विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए. अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतिम मुहर लगानी दी है जिसके बाद यह कानून बन गया है.

दो बिल जो संसद से पास हुए उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, और दूसरा

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 है.इन विधेयकों के खिलाफ हरियाणा-पंजाब के किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इसको लेकर किसानों की अलग-अलग आशंकाएं हैं.किसानों का मानना है कि यह विधेयक धीरे-धीरे एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) यानी आम भाषा में कहें तो मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा.

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि सरकार डैच (न्यूनतम समर्थन मूल्य) समाप्त नहीं कर रही है और न ही सरकारी खरीद को बंद कर रही है.

वहीं, इन विधेयकों को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और इसके कारण एनडीए के सबसे पुराने साथी अकाली दल ने सरकार में अपने मंत्री पद को भी त्याग दिया है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध करती आई है. राहुल गांधी ने यह भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं.

निजी कंपनियां कैसे आएंगी?

आइये जानते हैं कि कैसे इन बिलों के कारण भविष्य में निजी कंपनियों की मनमानी को लेकर आशंकाएं खड़ी हो रही हैं.

पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 है जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी.इसमें यह बात याद रखने वाली है कि सरकार का कहना है कि वह एपीएमसी मंडियां बंद नहीं कर रही है बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह निजी खरीदार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सके.

दूसरा बिल कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 है. यह कानून कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए है.

ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है.आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के आने के लिए यह एक ढांचा मुहैया कराएगा.

निजी कंपनियों के लिए एमएसपी?

बिहार के चंपारण के एक किसान श्री देवेन्द्र मिश्र कहते हैं कि सरकार ने जो भी कानून में कहा है वैसा तो पहले भी होता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अपनी फसलों को बाहर बेचने जैसी चीजें पहले भी होती रही

हैं और यह बिल सिर्फ अंबानी-अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ देने के लिए लाया गया है.वे कहते हैं, किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो कोई विवाद होने पर वह सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है जबकि पहले वह कोर्ट जा सकता था.

इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई. इससे तो लगता है कि सरकार किसानों को बांध रही है और कॉर्पोरेट कंपनियों को खुला छोड़ रही है. उन्हें अब किसी फसल की खरीद के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है.वहीं, इस कानून के बाद कोई भी कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है जो अच्छा है लेकिन इसमें एमएसपी की व्यवस्था कहां पर है? वो कहते हैं, मंडी के बाहर एमएसपी की व्यवस्था न होना ही सबसे बड़ा विवाद का बिंदु है. तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन इसमें मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है. अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए. उदाहरण के रूप में अगर गेहूं के लिए 1925 रुपये प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए. भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 6 फीसदी किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं. इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या है जिस कारण अधिक प्रदर्शन भी इन्हीं दो राज्यों में हो रहे हैं.देश में 23 फसलों पर ही एमएसपी है अगर एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए किया गया होता तो इससे देश के सभी राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचता और आगे उनके शोषण होने की आशंका कम हो जाती.

वहीं बीजेपी का कहना कै कि मंडी का कानून नहीं बदला गया है और मंडी में काम करने वाले लोगों और आढ़तियों ने ही किसानों को अपने यहां फसल बेचने के लिए मजबूर कर रखा था.देश का किसान अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है. आढ़तियों के पैसे के दम पर प्रदर्शन करके देश को गुमराह किया जा रहा है. लाखों किसान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं.

मंडी सिस्टम खत्म कर देंगी कंपनियां?

किसान श्री देवेन्द्र मिश्र कहते है कि मंडी सिस्टम समाप्त होने का डर जताते हैं. वो कहते हैं कि एक साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में आपसे फसल खरीदेंगी, उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो कॉर्पोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर फसल की खरीद करेंगी. बिहार राज्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहां मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालत ठीक नहीं है और उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जाती है, सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वह किसानों से सीधे फसल लेकर निजी कंपनियों को बेचे. मंडी सिस्टम खत्म करने की आशंका पर बहुतों की अलग राय है. वो कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और उस राशन को तो किसानों से ही खरीदा जाता है, सरकार कल भी इस राशन को खरीदेगी तो मंडियां कैसे बंद हो जाएंगी. बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया था. इससे अनुमान लगाया गया था कि किसानों को राज्य में अपनी फसल अपने मनपंसद दामों में बेचने में मदद मिलेगी.बिहार का हवाला देते हुए कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर किसानों को लेकर बाजार की हालत ठीक होती तो अभी तक बिहार के हालात क्यों नहीं सुधरे हैं, वहां पर प्राइवेट मंडियां, निवेश आदि की बात कही गई थी लेकिन हर साल वहां के किसान अपनी फसल लाकर पंजाब-हरियाणा में बेचते हैं.एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसी शंकाओं पर यह मजबूती के साथ कहा जा सकता हैं कि यह जोर का झटका धीरे से है क्योंकि एपीएमसी मंडियां खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं. एक ज्वलंत उदाहरण हैं, पंजाब में सबसे बड़ा मंडियों का नेटवर्क है. वहां पर जो बासमती चावल के निर्यातक हैं वे यह अब कह रहे हैं कि जब तक मंडियों का 4.50 फीसदी टैक्स हटा नहीं दिया जाता तब तक वे सामान बाहर से खरीदेंगे क्योंकि बाहर कोई टैक्स नहीं है. इसी तरह कपास और दूसरे सामान के निर्यातक कह चुके हैं कि वे मंडी से सामान नहीं खरीदेंगे. मंडी से टैक्स नहीं आएगा तो सरकार को कमाई नहीं होगी और कमाई नहीं होगी तो मंडियों का रखरखाव बंद हो जाएगा.

प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है कि जब मंडियां समाप्त हो जाए तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, किसानों का डर भी यही है. जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगी.

एमएसपी देने से क्या होगा?

भारत में किसानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है. वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते हैं और फिर उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है. 2015-16 में हुई कृषि गणना के अनुसार देश के 86 फीसदी किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है या यह वे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है.कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना जब अमरीका और यूरोप में फेल हो गई तो भारत में कैसे सफल होगी, वहां के किसान तब भी संकट में हैं जबकि सरकार उन्हें सब्सिडी भी देती है.कानूनी रूप से एमएसपी सभी के लिए लागू करने को देविंदर शर्मा भी सही मानते हैं.वो कहते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स कृषि क्षेत्र में जरूर आएं लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एमएसपी को एक कानूनी उपाय बना दिया जाए. निजी कंपनियां कह रही हैं कि वो किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम देंगे. सरकार, अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं तो फिर इसे कानूनी रूप क्यों नहीं पहना दिया जाता कि इतने से कम दाम में किसी फसल की खरीदारी नहीं होगी.एमएसपी को अगर कानूनी जामा पहना दिया गया तो किसान खुश रहेगा. अमरीका में अगर किसानों के लिए ओपन मार्केट इतना अच्छा होता तो वहां पर किसानों को सब्सिडी क्यों दी जा रही होती.

कृषि बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर डरे हुए क्यों हैं किसान?

राज्यसभा में पारित हुए नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने का फैसला किया है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने सोमवार को इसके लिए मंजूरी दे दी है. कृषि मंत्री ने रबी की छह फसलों की नई एमएसपी जारी की है. ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कृषि संबंधी नए विधेयकों को लेकर किसान चिंतित हैं कि इससे मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर पड़ने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेकर ट्वीट किया,बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को सशक्त करेगा और उनकी आय दोगुनी करने में योगदान देगा. संसद में पारित कृषि सुधारों से संबंधी कानून के साथ-साथ बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा. जय किसान! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की ओर से इस बात के आश्वासन के बावजूद कि नए कानून से एमएसपी पर असर नहीं पड़ेगा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसान इन विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.इन तीनों बिलों को लेकर अलग अलग तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं. किसानों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर काफी संवेदनशीलता देखी जा रही है.

हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को प्रियंका गांधी ने लगाया गले

हाथरस में हुए गैंगरेप और हमले की घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी , कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (च्तपलंदां ळंदकीप) हाथरस पहुंचे और लड़की के पीड़ित परिवार से मिले. पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी ताकत हमें चुप नहीं करा सकती.

प्रियंका ने हाथरस के लिए कार की कमान हाथ में ली, बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी

हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जब शनिवार शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस की ओर रवाना हुए तो कार की ड्राइविंग सीट पर पार्टी महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी नजर आईं. सफेद रंग की टोयोटा कार की कमान प्रियंका ने खुद संभाल रखी थी. राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे थे.

जैसे ही राहुल (तैनस ळंदकीप) और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की खबर मिली तो यूपी प्रशासन ने डीएनडी टोल नाके को बंद कर दिया था. जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उन्हें रास्ता दे दिया गया लेकिन उससे पहले वहीं मौजूद कांग्रेस कार्यकताओं की भीड़ पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया. राहुल और प्रियंका को इस शर्त के साथ जाने की अनुमति दी गई कि अधिकतम पांच लोग जा सकते हैं.

दरअसल, भारी हंगामे के बाद यूपी सरकार ने दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (क्छक) से प्रियंका-राहुल की कार को रवाना होने की इजाजत दी, लेकिन बाकी कांग्रेस कार्यकताओं को डीएनडी फ्लाईओवर से आगे नहीं जाने दिया गया. यह दूसरा मौका है, जब दोनों नेता हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं. दो दिन पहले उन्हें हाथरस से काफी पहले हाईवे पर ही रोक लिया गया था. प्रियंका गांधी को सिल्वर टोयोटा कार को चलाते हुए हाथरस की ओर निकलीं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ड्राइविंग सीट पर बैठीं प्रियंका की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. प्रियंका नीले रंग की पोशाक में और राहुल गांधी सफेद कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए, दोनों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और इस दौरान बेहद शांत नजर आए. कार की पिछली सीट पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चैधरी, दलित नेता पीएल पुनिया और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठे थे.

वहीं यूपी पुलिस के एडीजी लव कुमार ने कहा कि हमने राहुल और प्रियंका गांधी सहित सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी है. राहुल गांधी के साथ कुछ कार्यकर्ता आगे जाने के लिए अड़े हुए थे. लिहाजा हल्का बल प्रयोग किया गया है. राहुल गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाएगा. यूपी पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोकेगी. कानून व्यवस्था के लिए ट्रैफिक रोका गया है. थोड़ी देर में सब बैरियर खोल दिए जाएंगे.

दिल्ली से हाथरस की दूरी करीब 200 किलोमीटर है.इससे पहले राहुल गांधी ने आज दोबारा हाथरस जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि कोई भी ताकत उन्हें पीड़िता के परिजन से मिलने से नहीं रोक सकती. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस अडिग रुख के बाद यूपी सरकार के रवैये में बदलाव देखा गया है. दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (क्मसीप-छवपकं ठवतकमत) पर मौजूद भारी

संख्या में पुलिस बल ने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकताओं पर लाठीचार्ज भी किया. कांग्रेस कार्यकताओं का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन लाठीचार्ज से वे डरने वाले नहीं हैं.

प्रियंका गांधी वाड्रा कवच बनकर आ गईं सामने, जब क्छक पर कांग्रेस कार्यकर्ता पर हुआ लाठीचार्ज

इस बीच प्रियंका ने एक लाठी को भी पकड़ लिया. इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेता को पुलिस की लाठियों से बचाते हुए सड़क के बीच से थोड़ा साइड में लेकर गईं और उन्हें बैठा दिया.

नई दिल्लीरू यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने की मांग पर अड़े हुए कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को तो यूपी पुलिस ने जाने की अनुमति दे दी लेकिन इससे पहले डीएनडी पर एक हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. शनिवार को प्रियंका गांधी खुद गाड़ी चलाकर डीएनडी पहुंची साथ में राहुल गांधी बैठे हुए थे. उनके पहुंचते ही ये हाईवोलटेज ड्रामा शुरू हो गया, काफी कहासुनी के बाद यूपी पुलिस ने राहुल प्रियंका समेत पांच लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी. लेकिन कुछ कार्यकर्ता नहीं माने तो यूपी पुलिस ने लाठियां भी भांजी. लेकिन प्रियंका गांधी खुद गाड़ी से उतरकर अपने कार्यकर्ता को बचाने आ पहुंची यहां तक पुलिसवाले की लाठी भी पकड़ ली.

कवच बनकर सामने आ गईं प्रियंका

उस वक्त प्रियंका की गाड़ी ठीक टोल के बैरियर पर थीं. वहां पर कुछ कार्यकताओं ने जिद की अपने नेताओं के साथ जाने की. इसके बाद पुलिस ने कार्यकताओं पर

भारी हंगामे के बाद यूपी सरकार ने दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (क्छक) से प्रियंका-राहुल की कार को रवाना होने की इजाजत दी, लेकिन बाकी कांग्रेस कार्यकताओं को डीएनडी फ्लाईओवर से आगे नहीं जाने दिया गया. यह दूसरा मौका है, जब दोनों नेता हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं. दो दिन पहले उन्हें हाथरस से काफी पहले हाईवे पर ही रोक लिया गया था. प्रियंका गांधी को सिल्वर टोयोटा कार को चलाते हुए हाथरस की ओर निकलीं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ड्राइविंग सीट पर बैठीं प्रियंका की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. प्रियंका नीले रंग की पोशाक में और राहुल गांधी सफेद कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए, दोनों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था ।

लाठी चार्ज किया. इसे देखकर प्रियंका गांधी वाड्रा गाड़ी से उतरीं और उन्होंने तुरंत कांग्रेस नेता को बचाया. इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर को पुलिस की लाठियों से बचाया.

इस बीच उन्होंने एक लाठी को भी पकड़ लिया. इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेता को पुलिस की लाठियों से बचाते हुए सड़क के बीच से थोड़ा साइड में लेकर गईं और उन्हें बैठा दिया.

इससे पहले डीएनडी पर सैंकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकताओं को राहुल गांधी ने समझाया कि पुलिस ने उन्हें हाथरस जाने की अनुमति दे दी है और अब आप हमें आगे आने दें और पुलिस के साथ सहयोग करें. राहुल गांधी ने कार्यकताओं से कहा है कि पीएल पुनिया, गुलाम नबी आजाद, प्रमोद तिवारी को भी आगे जाने दें. लेकिन कार्यकर्ता नहीं हटे तो डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकताओं को हटाने के लिए यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जमीन पर पड़े कार्यकर्ता को उठाने के लिए गईं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चैधरी ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका जी को भी लाठी मारी है.

राहुल गाधी और प्रियंका गांधी गाड़ी से बाहर है और चोटिल पूर्व सांसद को देखा. इसके बाद कांग्रेस कार्यकताओं ने कहा कि वो यहां से नहीं जाएंगे. थोड़ी देर के हंगामे के बाद अब राहुल और प्रियंका डीएनडी से आगे निकल गए हैं.

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिलने को राहुल गांधी बड़ी जीत बताया. उन्होंने बीजेपी द्वारा इसे फोटो खिंचवाने का मौका करार देने पर हमला करते हुए कहा कि जब स्मृति ईरानी चूड़ियां भिजवा रहीं थी तो क्या वो भी फोटो खिंचवाने के लिए भेज रही थी.

सुरजेवाला ने मांगा योगी का इस्तीफा

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी अकेले पैदल चलकर जाने को भी तैयार थे. कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सीएम योगी इस्तीफा दे.

क्या कड़े निर्णय के चक्कर में देश को गर्त में पहुंचा दिया मोदी ने?

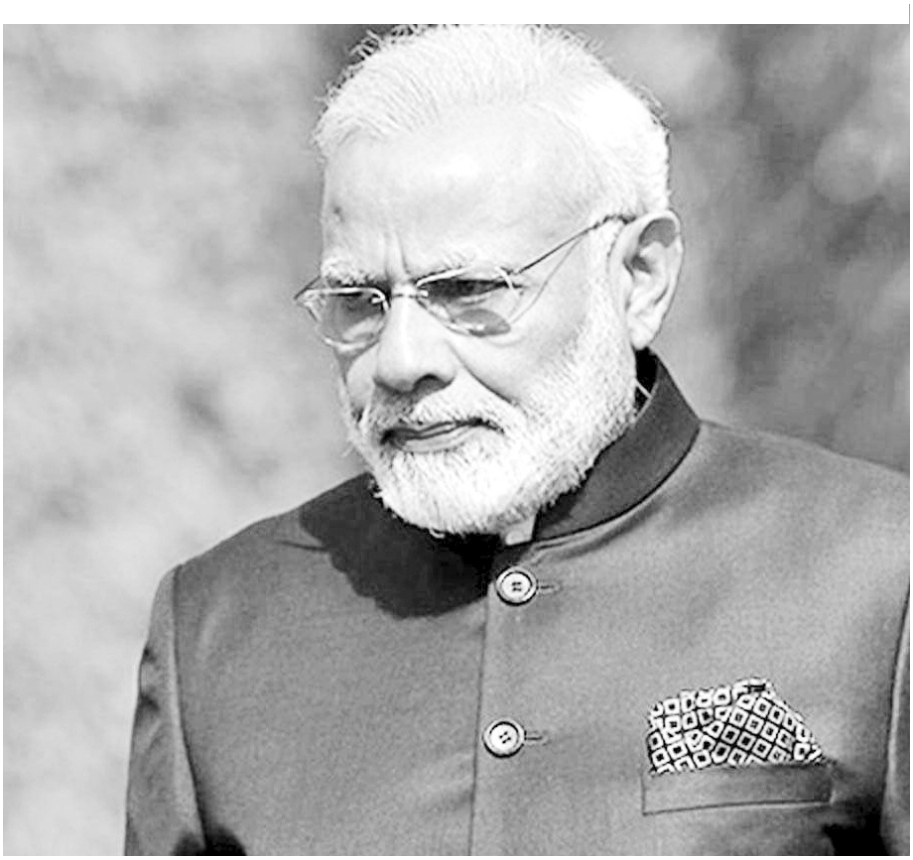

नोटबंदी और तालाबंदी ये दो ऐसे निर्णय हैं जिन्हें कड़े निर्णय की श्रेणी में रखा गया. दोनों निर्णयों ने अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए बर्बाद कर दिया. आर्थिक तबाही से त्रस्त लोग क्या यह सवाल पूछ पाएँगे कि जब आप तालाबंदी जैसे कड़े निर्णय लेने जा रहे थे तब आपकी मेज पर किस तरह के विकल्प और जानकारियाँ रखी गईं थीं.

भारत के सामाजिक-राजनीतिक मानस में एक हीनग्रंथि है. कड़े निर्णय लेने और भाषणबाज नेता का कांप्लेक्स इतना गहरा है कि यह भारत गांधी जैसे कम और साधारण बोलने वाले को ही नकार देता. नरेंद्र मोदी को जनता के बीच कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में स्थापित किया गया. मोदी ने भी खुद को कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में पेश किया. हर निर्णय को कड़ा बताया गया और ऐतिहासिक बताया गया. उन निर्णयों से पहले संवैधानिक नैतिकताओं को कुचल दिया गया. मुख्यमंत्रियों से पूछा जा सकता था कि क्या क्या करना है. उन्हें ही तालाबंदी की खबर नहीं थी. जनता के बीच उसे भव्य समारोह के आयोजन के साथ पेश किया गया ताकि कड़ा निर्णय चकाचैंध भी पैदा करे. नोटबंदी और तालाबंदी ये दो ऐसे निर्णय हैं जिन्हें कड़े निर्णय की श्रेणी में रखा गया. दोनों निर्णयों ने अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए बर्बाद कर दिया. आर्थिक तबाही से त्रस्त लोग क्या यह सवाल पूछ पाएँगे कि जब आप तालाबंदी जैसे कड़े निर्णय लेने जा रहे थे तब आपकी मेज पर किस तरह के विकल्प और जानकारियाँ रखी गईं थीं. उस कमरे में किस प्रकार के एक्सपर्ट थे? उनका महामारी के विज्ञान को लेकर क्या अनुभव था? या इसकी जगह आपने दूसरी तैयारी की. टीवी पर साहसिक दिखने और कड़े भाषण की? यह जानना बेहद जरूरी है.विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न तब और न आज कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए तालाबंदी करें. कोरोना एक महामारी थी. कड़े निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका नहीं था. इसकी जगह वैज्ञानिक निर्णय लेने थे लेकिन उससे मतलब तो था नहीं. जबकि विदेश से आने वाले कोई पाँच लाख यात्री थे. बिना देश को बंद किए इन पाँच लाख लोगों की जाँच और संपर्कों का पता कर आराम से रोका जा सकता था. उसके बाद भी हालात बिगड़ते तो दूसरे तरह के उपाय किए जा सकते थे.यह सब कुछ नहीं किया गया. पूरे देश को ठप्प करने के बजाए पाँच लाख लोगों की ट्रेसिंग हो सकती थी. वे किस किस से मिले इसका डेटा बन सकता था और सबकी टेस्टिंग कर उन्हें अलग किया जा सकता था.

30 जनवरी को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक चेतावनी जारी कर दी थी. उसकी किताब में सबसे बड़ी चेतावनी यही थी. मगर कड़े निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री उस समय कोरोना को कुछ न समझने के कड़े निर्णय ले रहे थे. यानी फरवरी महीने में अहमदाबाद में ट्रंप की रैली का आयोजन करवा रहे थे. 13 मार्च को सरकार कहती हैं कि कोरोना के कारण भारत में हेल्थ इमरजेंसी नहीं है. 24 मार्च को प्रधानमंत्री अचानक से कड़े निर्णय लेते हैं और देश को बर्बाद कर देते हैं. उनकी वाहवाही होती है कि इस तरह के कड़े निर्णय मोदी ही ले सकते हैं. जबकि वह फैसला मूर्खता से भरा था.

तुरंत ही जश्न मनाया जाने लगा कि मोदी ने कड़ा निर्णय लिया है. लोगों की सहज धार्मिकता की आड़ में एकल दीप प्रज्ज्वलित जैसे नाटकों से कड़े निर्णय की मूर्खता को महानता में बदला गया. देश को सास बहू सीरीयल समझ चलाने की सनक आज सबकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है. करोड़ों लोग सड़क पर आ चुके हैं. नौकरियाँ खत्म हो गईं.

भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट -24 प्रतिशत हो गई. हिसाब लगाएँगे तो जीडीपी के अनुपात में कर्जे का अनुपात 90-100 प्रतिशत हो चुका होगा. इसे यूँ समझें कि अगर जीडीपी का आकार 100 रूपया है तो भारत सरकार का कर्जा 90-100 रूपया है. ऐसी स्थिति को दिवालिया हो जाना कहते हैं. बाहर से लंबे समय के लिए निवेश बंद हो जाते हैं. तो अब यहाँ से आपकी जिंदगी में आर्थिक बदलाव अच्छे नहीं होने जा रहे. नौकरियाँ नहीं होंगी तो लंबे समय तक नौजवानों को बेरोजगार रहना होगा. बिजनेस को खड़ा होने में कई साल लग जाएँगे. लोगों की बचत आँधी हो जाएगी. राहुल गांधी ने फरवरी में कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है तब आप हंसे थे. अब आप हंस भी नहीं पाएँगे.

कड़े निर्णय की एक प्रक्रिया होती है. यह छवि बनाने का खेल नहीं होता है. नोटबंदी और तालाबंदी विषम परिस्थितियों में लिया गया कड़ा निर्णय नहीं था. बल्कि इन तथाकथित कड़े निर्णयों के कारण वो विषम परिस्थितियाँ पैदा हो गईं जिनके कारण आपका भविष्य खतरे में पड़ गया है. जीडीपी के आँकड़े आए. कड़े निर्णय लेने वाले मोदी और उनकी सरकार के सारे मंत्री

कड़े निर्णय की एक प्रक्रिया होती है. यह छवि बनाने का खेल नहीं होता है. नोटबंदी और तालाबंदी विषम परिस्थितियों में लिया गया कड़ा निर्णय नहीं था. बल्कि इन तथाकथित कड़े निर्णयों के कारण वो विषम परिस्थितियाँ पैदा हो गईं जिनके कारण आपका भविष्य खतरे में पड़ गया है. जीडीपी के आँकड़े आए. कड़े निर्णय लेने वाले मोदी और उनकी सरकार के सारे मंत्री चुप हैं. कोई बोल नहीं रहा है.

चुप हैं. कोई बोल नहीं रहा है.

पहली तिमाही की जीडीपी -मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं

सावधान हो जाएं. आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें. बल्कि अब यही ठीक रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहिए. यह बबार्दी की ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार कर कुछ नहीं हासिल कर सकते.आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं. भारत की किसी भी पीढ़ी ने ये आंकड़े नहीं देखे होंगे. 5 अगस्त को नए भारत के उदय के बाद इन आंकड़ों ने रंग में भंग डाल दिया है. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी -23.9 प्रतिशत आई है. सावधान हो जाएं. आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें. बल्कि अब यही ठीक रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहिए. यह बबार्दी की ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार कर कुछ नहीं हासिल कर सकते. इसका मतलब है कि पढ़ने वाला और लिखने वाला दोनों में से कोई नहीं बचेगा. साधु मरिहें जोगी मरिहें, मरिहें संत कबीर. साधो...

अर्थव्यवस्था के बारे में अभी तक झूठ बोला जा रहा है. जो है उसे नहीं बोला जा रहा है. जो होगा या जो नहीं होगा उसके बारे में अनर्गल बातें हो रही हैं कि आपके जिले में पेठा बनता है या पुड़िया बनती है, खाजा बनता है या खिलौना बनाता है, उसके निर्यात से भारत आत्मनिर्भर बनेगा. कमाल है.

कोरोना से लड़ाई का एलान हुआ. 64, 500 से अधिक लोग मर गए. हम वो लड़ाई हार गए. देश को तमाम मुद्दों में भटकाया गया. अर्थव्यवस्था के इस हाल में नौजवान पीढ़ी और हम सभी किस हद तक बर्बाद होंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं. बेशक मोदी जी बिहार चुनाव की जीत के बाद वाहवाही में लग जाएंगे, उन्हें ऐसी वाहवाहियां बहुत मिली हैं मगर नतीजा क्या निकल रहा है. नतीजा यही निकल रहा है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं, जिनके पास नौकरी थी वो चली गई. जिनके पास है, वो जाने वाली है. गोदी मीडिया लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का खेल बंद हो जाना चाहिए.

नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया

यह दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग (टनल) है. इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है. उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण श्अटल सुरंग का आज (शनिवार, 03 अक्टूबर) हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन किया. यह दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग (टनल) है. इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है. उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी चार से पांच घंटे कम हो जाएगा. 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी. पहले घाटी करीब छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी.

पीएम मोदी उद्घाटन समारोह के बाद लाहौल स्पिति के सीसू में दोपहर 12 से 12.45 तक एक जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद वो 12.50 पर वापस टनल होकर सोलंगनाला पहुंचे और भाजपा नेताओं को संबोधित किया. हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर सुरंग को बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि घोड़े की नाल के आकार वाली दो लेन वाली सुरंग में आठ मीटर चैड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है. उन्होंने बताया कि 3,300 करोड़ रुपए की कीमत से बनी सुरंग देश की रक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है. अटल सुरंग का डिजाइन प्रतिदिन तीन हजार कारों और 1500 ट्रकों के लिए तैयार किया गया है जिसमें वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. सुरंग में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई हैं. बता दें कि रोहतांग दर्रे के नीचे इसको बनाने का फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था. इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी. पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इस सुरंग का नाम उनके नाम पर रखा है.

नीतीश को फिर मुख्यमंत्री बनाने की 'साजिश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कुछ हद तक लोजपा नेता चिराग पासवान की साजिश को समझना होगा कि कैसे इन्होंने अपने अलग-अलग निर्णय से नीतीश कुमार की वापसी तय कर दी है.

बिहार में दो से तीन महीने के दौरान विधानसभा चुनाव होंगे. इस बार मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए बनाम विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है. अभी तक के जो भी रुझान हैं उससे नीतीश कुमार अपने साथ चुनावी अंकगणित और सामाजिक समीकरण दोनों में तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहे हैं. लेकिन अगर नीतीश कुमार की पंद्रह वर्षों के बाद सत्ता में वापसी तय है तो इसके पीछे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कुछ हद तक लोजपा नेता चिराग पासवान को समझना होगा कि कैसे इन्होंने अपने अलग-अलग निर्णय से नीतीश कुमार की वापसी तय कर दी है.

हालांकि इस बार एनडीए समर्थक वोटरों में नीतीश को लेकर वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो पिछले दो विधानसभा चुनावों में दिखा था. लेकिन चुनाव के सभी पैमाने पर जब तैयारी की बात हो या हर वर्ग के लोगों के लिए उनकी मांग मानने की बात हो तो नीतीश सजग और सतर्क दिखते हैं. हालांकि उनकी लोकप्रियता अब वैसी नहीं रही क्योंकि पहले वो किसी को चुनौती देते थे लेकिन अब वो जीत कर एक मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखते. लेकिन उन्हें ये मालूम है कि बिहार की राजनीति में विकल्प का अभाव है. तेजस्वी के सामने उनकी अपनी कुछ चुनौतियां जिनसे वो घिरे हुए हैं. बिना इनसे पार पाए तेजस्वी के लिए नीतीश को टक्कर देना आसान नहीं दिख रहा है. इसके अलावा जो अन्य दल चुनावी मैदान में हैं उनके पास जोड़ने के लिए ना तो आधारभूत वोट हैं न कार्यकताओं की फौज.

बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'साजिश'

भले पिछले एक साल से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में बैठे लोग बार-बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाने की बात दोहराते हैं लेकिन निजी बातचीत में दिल्ली से लेकर पटना तक वो आपको ये भी कहेंगे कि उनके खलिफ नाराजगी है. बीजेपी समर्थित एक वर्ग हमेशा नीतीश के बिना चुनाव में जाने का खयाली पुलाव पकाता रहता है. खासकर वो कोरोना का उदाहरण देते हैं, या कैसे श्रमिकों की वापसी का मुद्दा नीतीश ने ठीक से हैंडल नहीं किया. लेकिन ये भी सच है कि जिस मामले में नीतीश सरकार की सबसे अधिक फजीहत होती है उस विभाग में बीजेपी का का कोई वरिष्ठ नेता ही होता है. यही हाल स्वास्थ्य विभाग का भी है जहां ठश्रच के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे मंत्री हैं. लेकिन बिहार देश में एकमात्र राज्य होगा जिसके कोरोना वायरस के आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं करता. डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद त्ज्च्ब्त मशीनों के अभाव में 90ज से अधिक जांच एंटीजेन से होती हैं. हालांकि ठश्रच के नेताओं का कहना है कि नीतीश के शासन में मंगल पांडे की औकात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके विभाग के प्रधान सचिव की नियुक्ति या नाम की जानकारी उन्हें स्थानीय चैनल के माध्यम से होती है.लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के छह वर्ष बाद जिस पटना शहर में दानापुर से पटना सिटी तक बीजेपी के एक नहीं पांच-पांच विधायक पिछले बीस वर्षों से लगातार जनता द्वारा चुने जा रहे हों , दो-दो सांसद बीजेपी के हैं, नगर विकास मंत्री बीजेपी का , मेयर बीजेपी की उस पटना का यह हाल है कि केंद्र सरकार के स्वच्छता सूचकांक में सबसे फिसड्डी या सबसे अंतिम पायदान पर है. यह किसी भी पक्ष का आरोप नहीं है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पिछले सप्ताह की रैंकिंग का सच है.जबकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब क्षेत्र से चुने गए हैं. लेकिन ये रैंकिंग न केवल बीजेपी विधायक, सांसदों , मंत्री की सामूहिक विफलता है बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रबंधन और नेतृत्व के बावजूद बीजेपी क्यों आज तक नीतीश का विकल्प नहीं बन पायी है. खुद भाजपा के नेता स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो नीतीश कुमार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा न देकर एक तरह से संदेश दे दिया कि वो बिहार में राजनीतिक आधार बढ़ाने के बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं और उनका कहना है कि भले लोगों को लगे कि नीतीश कुमार की

बेइज्जती हुई. बल्कि उसका संदेश बिहार के लोगों को यही गया कि शायद नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा बिहार के लोगों को सम्मान देने में विश्वास नहीं करते.इसके अलावा 5 साल पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी लेकिन सच्चाई यही है कि इस पैकेज के अधिकांश प्रोजेक्ट पर अभी भी काम जमीन पर शुरू नहीं हो पाया है और गांधी सेतु के एक हिस्से का रिपेयर कर शायद आप बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बन सकते. इस पुल के समानांतर एक और प्रस्तावित पुल का टेंडर पांच वर्षों में अब जाकर पूरा हो पाया है और शायद चुनाव की घोषणा के ठीक पहले इसका शिलान्यास किया जाए.बाढ़ हो या सूखा कभी भी पिछले कुछ सालों में नहीं लगा कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य पर मेहरबान है. जैसे बाढ़ की समस्या के निदान की नीतीश ने बात की तो केंद्र ने उनके सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया. जिससे लगा कि डबल इंजन की सरकार नाम मात्र के लिए है. अब तो बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि ये सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जिससे यही लगता है कि अगर नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की कोई साजिश रची गई हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सब सुस्त रवैए से उसमें शामिल रहे हैं.

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनावों तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद की संयुक्त उम्मीदवार थे उनकी दिक्क़त यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जिस प्रकार से लंबा दिल्ली में प्रवास किया उससे बिहार की राजनीति में उनकी गंभीरता ना केवल कम हुई बल्कि उनके बारे में तरह तरह के सवाल भी किए जाने लगे कि कोरोना के बाद भी तेजस्वी पटना में नहीं थे लेकिन बाद में वो आए और सक्रिय हुए. बाढ़ के दौरान भी वो पटना से निकलें तो जरूर लेकिन जैसी परिस्थिति बनी थी और उसमें जैसा विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ. ये बात तेजस्वी के कट्टर समर्थक भी मानते हैं. एक दिन के विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने सरकार को जमकर घेरा लेकिन बिहार की राजनीति का ये भी सच है कि दौरा, भाषण , सोशल मीडिया में सक्रियता से बिहार में वोट नहीं बढ़ता. ये सच उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी के बदले उस कुर्सी पर बैठे सुशील मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता.तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी दिक्क़त यह है कि चुनाव सर पर है लेकिन अभी तक वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार नहीं बन पाये हैं. जो सहयोगी हैं वो संवादहीनता की शिकायत करते हैं. उनके लिए सीटों का तालमेल करना उतना आसान होगा क्योंकि ये गठबंधन में जितने अधिक दल होते हैं उतनी ज्यादा माथापच्ची इन सभी चीजों पर करनी होती है. हालांकि पार्टी का काम वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह बखूबी निभा रहे हैं. लेकिन देखना यह है कि जब टिकट देने की बारी आयेगी तो उनकी कितना चलेगी. इस पर चुनाव का परिणाम तय हो जायेगा. अगर टिकट में लालू यादव के परिवार का दबदबा रहा तो आप समझ लीजिए कि चुनाव में नीतीश कुमार को वॉक ओवर मिल जाएगा. लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह या शिवानंद तिवारी की तरफ से चुनाव से पहले मिल रहे संकेत तेजस्वी के लिए शुभ नहीं है. इसके अलावा तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती अपना घर ठीक रखना है क्योंकि उनके घर में जितने राजनीतिक रूप से सक्रिय सदस्य हैं वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करते रहते हैं. जैसे उनक बड़े भाई तेज प्रताप यादव जब भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं , बयान देते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि इनसे अच्छी तो नीतीश कुमार की सरकार ही है.लेकिन इन सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव के हाव भाव से नहीं लगता कि उनमें फिलहाल सता की भूख है. इसलिए वो अगर इस चुनाव में पिछली चुनाव में मिली सीटों में से पचास प्रतिशत भी जीत लें तो एक बड़ी उपलब्धि होगी. इस आधार पर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी भी जानबूझकर नहीं लेकिन अपने आलसपन से नीतीश कुमार को फिर सत्ता में बैठाने की 'साजिश' में शामिल हैं. लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है ये बात किसी से छिपी नहीं. पिछले आठ महीनों के दौरान चिराग कोई एक ऐसा मौका नहीं चूकते जहां नीतीश कुमार की आलोचना करने का गुंजाइश न हो. लेकिन हर बार पत्र लिखकर और उसे सार्वजनिक कर चिराग पासवान ने कहीं न कहीं नीतीश कुमार को दलित वोटरों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए इस बार मौका दिया. इसका परिणाम है कि हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पार्टी में नीतीश या पर किसी दलित नेता या अधिकारी को शामिल करते हैं. हालांकि एलजेपी में चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान को अलग-थलग करने की नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति रही है क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग उनको उनके खलिफ जितना बयानबाजी करेंगे उससे महादलित वोटरों में एक संदेश जाएगा. सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का भलीभांति आभास है कि बिहार की ऊंची जाति के वोट उनको मजबूरी में वोट देते हैं और जब तक उनके पास अति पिछड़ा महादलित और गैर-यादवों का समर्थन है तो उनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता.

नीतीश कुमार क्यों हैं अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त

पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच अभी तक दो कारणों से बिहार की चर्चा होती है. एक नीतीश कुमार एक मात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले साढ़े पांच महीने में एक भी बार इस मुद्दे पर पत्रकारों से रूबरू नहीं हुए और न ही कभी अपने राज्य की जनता को संबोधित किया. लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कोरोना संकट को आधार बनाकर लोगों के खाते में वो अभी तक 10, हजार करोड़ से अधिक पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं. जिससे कम से कम उनकी सीधी पहुंच दो करोड़ से अधिक परिवार में हुई है.

वो चाहे बच्चों के खाते में पैसा हो या हर राशनकार्ड धारियों के खाते में 1 -1 हजार रुपया हो, या एक साथ तीन महीने का पेंशनधारियों को पेंशन की राशि ट्रांसफर की गई हो, या छात्रों को छात्रवृत्ति की पाई-पाई उनके खाते में भेजना हो... चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार के लिए यह सब तुरुप का पत्ता जैसे काम कर रहे हैं. यह भी सच है केंद्र द्वारा भी जनधन खाते में पैसा हो या मुफ़्त राशन, लोगों की नौकरियां जाने के बावजूद अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों में असंतोष नहीं दिख रहा है. लोग नीतीश सरकार की लाख कमियां गिना रहे हैं लेकिन जनता उन्हें फिर से वोट देने की बात कर रही है. आज की बिहार की राजनीति का यही सच है. नीतीश को लेकर सबसे ज्यादा बहस मुस्लिम समुदाय में हैं. क्योंकि अधिकांश के इस वर्ग के लोगों को यही लगता है कि वो भले ही राजद के साथ हैं लेकिन नीतीश ने कभी भी इस समुदाय के लोगों से भेदभाव नहीं किया और वो जब तक सत्ता में ही तब तक राजद का बिहार की सत्ता में आने का मंसूबा धरा का धरा रहेगा. इसलिए कम से कम उनके खलिफ आक्रामक बैटिंग न की जाए और जहां भी उनका उम्मीदवार हो तब उसे वोट देने में हिचक भी नहीं बरतनी चाहिए. बार-बार भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद भी भागलपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के आरोप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चैबे के पुत्र को जेल भेजने की घटना का जिक्र मुस्लिम समुदाय के लोग करना नहीं भूलते. वो गुस्साए नीतीश कुमार ही थे जो ऐसे कदम उठाने से भी नहीं हिचके. यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे उपद्रव कराने की मानसिकता के लोग सहमे रहते हैं. लेकिन बिहार के चुनाव में एनडीए की चुनौती 2010 के परिणाम से बेहतर करने की होगी. जब 243 में 206 सीटें नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को मिली थी. इसके अलावा देखना यह भी है कि किस पार्टी का स्ट्राइक रेट एक दूसरे से बेहतर रहता है.

बिहार बीजेपी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है, जबकि चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार को बनाया गया है.

जदयू ने शुरू किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 10 लाख लोगों तक जुड़ सकेंगे सीएम नीतीश कुमार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार अधिकतम 10 लाख लोगों तक जुड़ सकते हैं. बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के मुताबिक जेडीयू देश की ऐसी पहली पार्टी बन गई है, जिसका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है.बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है. वहीं अब चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत की है. पटना के पार्टी ऑफिस के नए कपूर्री सभागार में इसकी शुरूआत की गई. इस दौरान जेडीयू के सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और अशोक चैधरी मौजूद थे. जेडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं.इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार अधिकतम 10 लाख लोगों तक जुड़ सकते हैं. बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के मुताबिक जेडीयू देश की ऐसी पहली पार्टी बन गई है, जिसका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है. उसे जूम या गूगल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए जेडीयू जोर-शोर से तैयारियां कर रही है.

फिर से रफ्तार पकड़ने लगी हैं देश में आर्थिक गतिविधियां

पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प पड़ गई थीं। भारत भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रहा था। लॉकडाउन के चलते, मार्च 2020 के बाद से लगातार आर्थिक गतिविधियों में कमी देखने में आई थी। परंतु अब हर्ष का विषय है कि माह सितम्बर 2020 में देश में आर्थिक गतिविधियों ने वापिस रफ़्तार पकड़ ली है। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र के सम्बंध में सही समय पर लिए गए कई निर्णयों के चलते ही यह सम्भव हो सका है।

माह सितम्बर 2020 में देश में ऊर्जा की माँग, माह सितम्बर 2019 की तुलना में,3 प्रतिशत बढ़ गई है। जबकि अगस्त 2020 में ऊर्जा की माँग, अगस्त 2019 की तुलना में, 2 प्रतिशत कम थी। ऊर्जा की माँग में माह सितम्बर 2019 की तुलना में माह सितम्बर 2020 में वृद्धि होना, दशार्ता है कि देश में उत्पादन गतिविधियों में तेजी आई है। इसी प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि एवं कमी दशार्ने वाला इंडेक्स (पीएमआई) भी माह सितम्बर 2019 के 51.4 की तुलना में माह सितम्बर 2020 में बढ़कर 56.8 हो गया है। इस इंडेक्स का 50 के अंक से अधिक होना दशार्ता है कि उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है एवं यदि यह इंडेक्स 50 के अंक से नीचे रहता है तो इसका आश्य होता है कि उत्पादन गतिविधियों में कमीं हो रही है।

माह सितम्बर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर की उगाही में भी अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। माह सितंबर 2019 में यह 91,916 करोड़ रुपए की रही थी जो माह सितम्बर 2020 में बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए हो गई है। यह माह अप्रेल 2020 में घटकर 32,172 करोड़ रुपए हो गई थी एवं माह मई 2020 में बढ़कर 62,151 करोड़ रुपए तथा माह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपए की रही थी।

देश में पेट्रोल की बिक्री भी माह जनवरी 2020 के 24,56,000 टन की तुलना में माह सितम्बर 2020 में 24,19,000 टन की रही है अर्थात कोरोना महामारी के पूर्व के स्तर को लगभग प्राप्त कर लिया गया है।

माह सितम्बर 2020 में यात्री वाहनों की बिक्री में भी उछाल देखने में आया है। यात्री वाहनों की बिक्री माह सितम्बर 2020 में 2.8 से 2.9 लाख वाहनों की रही है जो माह सितम्बर 2019 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

माह सितम्बर 2020 में भारतीय रेल्वे की आय एवं सामान की ढुलाई की मात्रा में भी तुलनात्मक रूप से अच्छी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। सामान की ढुलाई की मात्रा में, माह सितम्बर 2020 में, माह सितंबर 2019 की तुलना में, 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

की गई है। इसी प्रकार, सामान ढुलाई से आय में भी इसी अवधि में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है।

उक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि देश में अब उपभोक्ता वस्तुओं की माँग तेजी से बढ़ रही है। भारत के विदेशी व्यापार क्षेत्र से भी बहुत अच्छी खबर आई है। बहुत लम्बे समय के बाद, विदेशी व्यापार के चालू खाता में, वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही अर्थात अप्रेल से जून 2020 के बीच में, 1,980 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आधिक्य शेष दर्ज किया गया है। सामान्यतः भारत के विदेशी व्यापार के चालू खाता में कमी का शेष ही रहता आया है। विदेशी व्यापार के चालू खाता में आधिक्य शेष होने का आश्य यह है कि देश से निर्यात, आयात की तुलना में अधिक हो रहे हैं। जबकि सामान्यतः देश में आयात, निर्यात की तुलना में अधिक रहते हैं। साथ ही, देश के निर्यात में भी 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी दिनांक 18 सितम्बर 2020 को 54,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है एवं इसमें लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

इस वर्ष मानसून की वर्षा भी 28 सितम्बर 2020 तक सामान्य औसत से 9 प्रतिशत अधिक रही है। लगभग सभी राज्यों में सामान्य औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में, खरीफ सीजन में, कृषि पैदावार में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सामान्य औसत से अधिक वर्षा होने के चलते रबी सीजन में भी पानी की उपलब्धता सुधर जाएगी जिसके कारण रबी सीजन में भी कृषि पैदावार में अच्छी वृद्धि रहने की सम्भावना बढ़ गई है। जिसके चलते ट्रैक्टर, खाद, वाहनों, उपभोक्ता वस्तुओं, आदि की बिक्री में उछाल आने की पूरी सम्भावना रहेगी।

आने वाले माह अक्टोबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में त्योहारों के चलते भी वाहनों एवं उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में वृद्धि दर्ज होने की पूरी सम्भावना है, जिसके चलते वाहन उद्योग एवं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाईयों में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है।

कृषि क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र के कोरोना महामारी के पूर्व के स्तर पर आ जाने के बाद अब सेवा क्षेत्र से उम्मीद की जानी चाहिए कि यह क्षेत्र भी अपने पूर्व के स्तर को शीघ्र प्राप्त करे। हालाँकि अब केंद्र सरकार द्वारा धीरे धीरे सेवा क्षेत्र को भी खोला जा रहा है, जैसे कुछ रेलगाड़ियों को प्रारम्भ कर दिया गया है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोगों को आने जाने की छूट प्रदान कर दी गई है, मुंबई में लोकल ट्रेन को चालू कर दिया गया है एवं दिल्ली में मेट्रो की शुरूआत भी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उड़ानों को प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही, वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को, कुछ नियमों का पालन करते हुए, जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अंतरराज्यीय बसों को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। होटलों एवं अन्य मनोरंजन के स्थानों को भी, कुछ शर्तों के साथ, धीरे धीरे खोलने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

पहिले हर राज्य द्वारा क्वॉरंटीन सम्बंधी नियमों को अपने स्तर पर ही लागू किया जा रहा था, परंतु अब राज्य सरकारों को इन नियमों को लागू करने के पूर्व केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार पूरे देश में क्वॉरंटीन सम्बंधी नियमों में एकरूपता लाई जा रही है, ताकि नागरिकों में विश्वास बढ़े।

हालाँकि अब कुछ अच्छी खबरें भी आने लगी हैं। देश के कुछ होटलों में सप्ताह अंत के समय के लिए बुकिंग अब फुल होने लगी है। धीमे धीमे ही सही, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, घरेलू पर्यटन तो प्रारम्भ हो रहा है। यह अब और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आसपास के शहरों में ऐसे कई स्थान पाए जाते हैं जहाँ सप्ताह अंत में जाया जा सकता है।

ऐसे इलाकों में एवं देश के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ मौजूद है। अब लोग दरअसल अपने घरों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किए जा रहे प्रयासों के कारण ऐसा महसूस होने लगा है कि देश में अब घरेलू पर्यटन तो शीघ्र ही पुनर्जीवित हो जाएगा। इस प्रकार, सेवा क्षेत्र में भी तेज गति से विकास देखने को मिल सकता है।

मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली से मस्जिद हटाने के लिए याचिका दायर

राम लला को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने और अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के पश्चात

श्रीकृष्ण विराजमान भी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए हैं। श्रीकृष्ण विराजमान और स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नाम से मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में1968 के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व मस्जिद के बीच समझौते को अमान्य करार देने की मांग करते हुए 13.37 एकड़ की श्रीकृष्ण जन्मभूमि (मस्जिद सहित) पर मालिकाना हक मांगते हुए याचिका दायर की गई है। लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री व त्रिपुरारी त्रिपाठी, सिद्धार्थ नगर के राजेश मणि त्रिपाठी एवं दिल्ली निवासी प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला व शिवाजी सिंह सहित आधा दर्जन लोगों ने उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से मथुरा की एक अदालत में याचिका दाखिल कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच पांच दशक पूर्व हुए अवैध समझौते को निरस्त कर मस्जिद की पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने का अनुरोध अदालत से किया है।

याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से गलत और अवैध है तथा उसे निरस्त किया जाए। दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) छाया शर्मा की अदालत में दाखिल किए गए वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को जमीन देने को गलत बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (जो अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है) व शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर हुए समझौते में तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी । समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार याचिकाकताओं ने कहा है कि विवादित स्थल कत्रा केशव देव (ऐतिहासिक नाम) की 13.37 एकड़ भूमि का एक-एक इंच भगवान श्री कृष्ण के भक्त एवं हिंदू समुदाय के लिए पवित्र है । याचिका में दावा किया गया है कि श्रीकृष्ण का जम्मस्थान वास्तविक कारागार मस्जिद समिति के द्वारा बनाए गए निर्माण के नीचे ही स्थित है और वहां पर खुदाई होने पर सच्चाई का पता चलेगा। उन्होंने दावा किया कि सेवा संघ और मस्जिद समिति ने समझौता करके एक मानव-निर्मित कारागार बना दिया था, ताकि राजनीतिक कारणों के चलते लोगों से सच्चाई छिपाई जा सके । याचिकाकताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 तहत उन्हें अधिकार है कि वे भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन का देखरेख कर सकें । वादियों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता गलत है । इसलिए उक्त समझौते को निरस्त करते हुए मस्जिद को हटाकर मंदिर की जमीन उसे वापस करने की मांग की गई है। इस मामले में वादियों द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह ट्रस्ट प्रबंध समिति को भी प्रतिवादी बनाया गया है । इस संबंध में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने दायर किए गए वाद के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से परहेज करते हुए उन्होंने ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों व कानूनवेत्ताओं से परामर्श किए जाने के बाद उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है ।

बेटियों की असुरक्षा का जिम्मेदार कौन?

वाह रे राजनीति! अब शब्द ही नहीं बचे कि जिससे उदाहरण दिया जाए। कुर्सी की चाहत में आज सब कुछ कुर्बान! सत्ता के समीकरण में उलझा हुआ देश पूरी तरह से त्रस्त है। अब बस एक ही कार्य रह गया है वह है समीकरण! यह सत्य है कि समीकरण के फेर में जो भी फिट बैठता है वह दिन दूना रात चौगुना सत्ता की छांव के सहारे बुलंदियों की ओर कदम-ताल करता हुआ तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। यदि शब्दों को बदलकर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि सियासत की क्षत्र-छाया में आसानी के साथ प्रत्येक दुःख दूर हो जाते हैं। परन्तु अफसोस, दुर्भाग्यवश यदि सियासत की क्षत्र छाया न हो तो स्थिति ठीक विपरीत हो जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। पीड़ा कितनी भी हो दर्द कितना भी हो परन्तु वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। यह बड़ी चिंता का विषय है जो दृश्य उभरकर सामने आ रहा है वह बहुत ही भयावक है। आज क्या हो रहा है प्रत्येक स्थानों पर अपराध बढ़ रहा है जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जोकि एक साथ कई सवालों को जन्म देता है। अंकुश न लग पाने का कारण क्या है? इसे समझने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन एवं मनन करने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके पीछे छुपे हुए कारण को खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं वह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहन बेटियां हमारे समाज का मुख्य अंग है हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा हैं यह सोचने का विषय है यह समझने का विषय है इस पर सोचने समझने एवं मंथन करने की आवश्यकता है। आज जिन युवाओं को बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए आज वही युवा बहन बेटियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्या हमने कभी ऐसे समाज की परिकल्पना की थी? यह बड़ा सवाल है।

बेटियों के प्रति बढ़ते हुए अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हमारे मानव समाज का एक हिस्सा राक्षस रूपी मानसिकता की ओर तेज गति के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि, महिलाओं एवं बेटियों के प्रति बढ़ते हुए घिनौने अपराध ने जिस प्रकार से अपना राक्षस रूपी चेहरा देश के सामने प्रस्तुत किया है वह अत्यंत दुखद है। इसको रोकना आज समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है! क्योंकि, कठोर से कठोर कानून एवं नियम बना लेने से अपराध नहीं रुक सकता इसका मुख्य कारण यह है कि कानून एवं नियम की परिभाषा एवं कायदे कागज के पन्नों पर ही अंकित होते हैं न कि अपराधियों की मानसिकता पर। अपराधियों की मानसिकता पर कानून का खौफ क्यों नहीं होता यह बड़ा सवाल है? इस पर चिंतन एवं मनन करने की आवश्यकता है। आज बड़े से बड़ा अपराध करने वाले अपराधी बेखौफ क्यों होते जा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है! अपराधियों के अंदर कानून का डर न होना अपने आप में बड़ा सवाल है। आज कानून एवं नियम धरातल पर मजबूती के साथ लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? यह बड़ा सवाल है।

इसके पीछे का मुख्य कारण को खोजने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे किसी भी प्रकार का पक्षपात, जातिवाद, वर्चस्ववाद, अथवा किसी भी प्रकार का भ्रम एवं दबाव तो कार्य नहीं कर रहा क्योंकि आज अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है! जब तक अपराधियों के पीछे खडे हुए सहयोगी रूपी बड़ी ताकतों को मुख्य दोषी नहीं माना जाएगा तबतक अपराध नहीं रुक सकता। क्योंकि जबतक जड़ो पर मजबूती के साथ प्रहार नहीं होगा तबतक अपराध पर अंकुश लगा पाना असंभव है। क्योंकि अपराधियों का बढ़ता हुआ मनोबल यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इसके पीछे कोई अदृश्य बड़ी ताकतें हैं। क्योंकि बिना सहयोग एवं समर्थन के अपराधियों का मनोबल कदापि नहीं बढ़ सकता। ऐसा प्रत्येक प्रकार के अपराधों में सदैव ही देखा गया है। कि कुछ अदृश्य ताकतें अपने निजी स्वार्थ के लिए पीठ के पीछे खड़ी होती हैं।

हाथरस में जिस प्रकार की घटना हुई है उसने समस्त संसार को एक बार फिर से कठघरे में खड़ा कर दिया है क्योंकि जिस प्रकार से एक बेटी के साथ क्रूर एवं बर्बर तथा घिनौना अपराध किया गया वह अपने आपमें बहुत कुछ कह रहा है। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जोकि अपने चारों ओर सवाल बिखेर रहा है। सबसे पहले शासन एवं प्रशासन पर नजर जाती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद शासन एवं प्रशासन कहां खड़ा था? धरातल पर कानून रूपी देवता कहाँ खड़े थे? कानून के रखवालों ने अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार से निर्वहन किया। यह बड़े सवाल हैं। कानून के रखवालों ने पीड़ित परिवार का किस प्रकार से साथ दिया? क्योंकि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं! पीड़िता को तुरंत सर्वोत्तम उपचार की आवश्यकता थी परन्तु साधारण उपचार से ही कार्य को टरकाया गया। इस प्रकार की हीला-हवाली के पीछे का कारण क्या है? ऐसी कौन सी मजबूरी एवं ऐसा कौन सा दबाव था जिस कारण जिम्मेदारों ने मामले को गम्भीरता से नहीं लिया। जिस प्रकार से एक के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दिया जा रहा है यह बहुत ही चिंता का विषय है! निर्भया कांड की आवाज अभी धूमिल नहीं होने पाई थी कि हाथरस काण्ड ने पूरे समाज को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। हाथरस के साथ-साथ बलिया का कांड भी अपराधिक मानसिकता के मनोबल पर सवालिया निशान खड़े करता है। अपराधियों का इस प्रकार से बढ़ता हुआ मनोबल समस्त समाज को चैलेंज कर रहा है। ऐसा क्यों है? इस बढ़ते हुए मनोबल के पीछे खड़े इनके मददगार कौन हैं? इस बिन्दु पर कार्य करना बहुत जरूरी है।

आज भी बेहद प्रासंगिक हैं गांधी के विचार और सिद्धांत

आज सम्पूर्ण विश्व कोरोना नामक महामारी के घातक प्रकोप से जूझ रहा है, बहुत सारे देशों में आपसी मनमुटाव के चलते विश्व समुदाय पर बड़े युद्ध का अंदेशा हर वक्त मंडरा रहा है। विश्व में मानवीय संवेदनाओं व मानवीय मूल्यों में भारी गिरावट के चलते हर तरफ एक अजीब तरह का नफरत भरा माहौल बना हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग महत्वाकांक्षा व बेवजह के मसलों को लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस स्थिति के चलते इंसानियत का बेहद तेजी के साथ दिनप्रतिदिन क्षरण हो रहा है। यह स्थिति सम्पूर्ण मानव सभ्यता के लिए व अमनचैन पूर्ण माहौल के लिए बेहद चिंतनीय है। कुछ लोगों की वजह से समाज में हर तरफ एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता के चलते, आजकल अपराध छल-कपट झूठ-प्रपंच धन के दिखावे भरे आडंबर का जबरदस्त बोलबाला होता जा रहा है। इस स्थिति से हमारा प्यारा देश भारत भी बहुत तेजी के साथ ग्रसित होता जा रहा है। आजकल समाज में तेजी के साथ बढ़ते नफरत भरे माहौल से अब हमारे देश का सकून भरा माहौल व आम जनमानस भी अछूता नहीं रहा है। कही ना कही आम जनमानस के एक बहुत बड़े वर्ग की संकुचित सोच की वजह से, आज हमारे देश में भी गलत व नौटंकीबाज व्यक्ति समाज के एक वर्ग के लोगों को बेहद कामयाब होते नजर आ रहे हैं और बेहद अफसोस की बात यह है कि वो गलत लोग अब कुछ लोगों के आदर्श बनते जा रहे हैं। मौजूदा मंदी के दौर में देश में सर्वांगीण विकास को निर्बाध ढंग से चलाने के लिए हम लोगों को तत्काल आवश्यकता है कि हम देश में उत्पन्न इस स्थिति को देशहित व समाज के हित में तत्काल बदल डालें। हालात में सुधार करने के लिए देश में तत्काल आवश्यकता है कि हमारी सरकार व हम स्वयं भी अहिंसा के पुजारी आदरणीय महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचारों पर अमल करें। भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया के बुद्धिजीवी लोग नकारात्मकता से पूर्ण माहौल से निकालने के लिए अब फिर से महात्मा गांधी के दर्शन और उनके ओजस्वी विचारों की ओर देख रहे हैं। आज समय की जरूरत है कि हम उनके ओजस्वी व्यक्तित्व व विचारों से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर लोगों को एकबार फिर से समझाएं और अवगत कराये और उनको गांधीवादी विचारों की सत्यता से रूबरू करवाकर उनको रोजमर्रा की जिंदगी में धरातल पर अमल में लाने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित करें।

हालांकि यह भी जिंदगी का एक बेहद कटु सत्य है कि महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में बात बनाना बेहद आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बेहद कठिन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य-अहिंसा के पुजारी थे, वो उसका अपने रोजमर्रा के आचरण में अक्षरशः पालन करते थे, जो कि बहुत कठिन कार्य है। वैसे भी देखा जाये तो महात्मा गांधी जी ताउम्र साक्षात, दूरगामी सोच वाले महामानव, सादगी, सरलता,

सज्जनता, प्रकृतिप्रेमी, सत्य, अहिंसा, स्पष्टवादिता, समय का पालन करने वाले, धर्यवान, स्वच्छता प्रेमी, जबरदस्त संकल्प शक्ति, छूआछूत मिटाने वाले, कुटीर उद्योग के पक्षधर, स्वदेशी के पक्षधर, नस्लभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले, मान-सम्मान, स्वाभिमान, शालीनता, देश का गौरव बढ़ाने वाले, दृढसंकल्प, सहिष्णुता, मानसिक मजबूती, निडरता, आपसी भाईचारा निभाने वाले, इंसानियत को सर्वोपरि मानने वाले, करुणा, जीव प्रेम, ईमानदारी व देश प्रेम आदि बहूमूल्य गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। महात्मा गांधी जी जीवनपर्यंत निस्वार्थ भाव से आडंबर चमक-दमक, तड़क-भड़क, ईर्ष्या, द्वेष, प्रचार-प्रसार और बड़बोलेपन, दिखावे से हमेशा कोसों दूर रहकर मानव सभ्यता के उत्थान के लिए कार्य करते रहते थे। महात्मा गांधी जी ने हमेशा सादा जीवन उच्च विचार के अनमोल सिद्धांत को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात करके जिंदगी के अनमोल सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए आम जनमानस पर अपनी विशिष्ट अमिट छाप छोड़ी है। उनके अहिंसक मानवीय बदलाव के बेहद बृहद गांधीवादी दृष्टिकोण ने विश्व के तमाम देशों का धीरे-धीरे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर किया है।

भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आजकल जिस तरह से विश्व में नफरत के चलते हिंसा चरम पर है, नस्लभेदी दंगे आयेदिन चल रहे हैं, धार्मिक उन्माद चरम पर है, देशों के आपसी मतभेद चरम पर चल रहे हैं, महामारी कोरोना के चलते एकदम उत्पन्न हुई बेरोजगारी चरम पर है, रोजीरोटी के भयावह संकट से जनसमुदाय जूझ रहा है, आपदा के चलते चिकित्सा व्यवस्था बेहाल हैं, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हैं, महंगाई अपने चरम पर है, इस बेहद तनावपूर्ण हो चुके वातावरण में हर देश की जनता आयेदिन सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करके छटपटा रही है। ऐसे में हर समझदार व्यक्ति को हालात पर नियंत्रण बनाने के लिए महात्मा गांधी जी के बेहद अनमोल गांधीवाद और उनके अनमोल सिद्धांत याद तो आ रहे हैं। लेकिन अफसोस गांधी के अपने ही देश भारत में बहुत सारे लोग उनके विचारों की गंभीरता व प्रासंगिकता को अभी भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझकर करना नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह से देश में कुछ लोगों की जहरीली विचारधारा ने महात्मा गांधी से विचारों की असहमति के भयंकर उन्माद में उनकी हत्या तक कर दी थी, आज भी उसी विचारधारा के अनुयायी बहुत सारे लोग गांधी के विचारों को गांधी के अपने ही देश से साफ करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त के थपेड़े तो अच्छे-अच्छे लोगों को भी सुधार कर सब कुछ सिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज जैसे-जैसे विश्व में हिंसा बढ़ रही है, आर्थिक मंदी बढ़ रही है, लोग भरपेट भोजन के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग तेजी से छद्म राष्ट्रवाद व नफरत की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे विश्व की जनता को न केवल गांधीवाद व गांधी दर्शन याद आ रहा है, बल्कि आज के दौर में उसे आत्मसात करने की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी है। अब समझदारों के तो समझ में आने लगा है कि आज विश्व में बहुत सारे देशों के बीच उत्पन्न युद्धस्तर के तनाव, समाज में बढती नफरत, कोरोना महामारी टेंशन, तबाह होती अर्थव्यवस्था, लोगों के आपसी मनमुटाव व लोगों के मानसिक तनाव की वजह से जो बेहद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उस सबका समाधान महात्मा गांधी के विचारों में छिपा हुआ है। कटु सत्य तो यह है कि इंसान व इंसानियत की रक्षा और प्रथ्वी पर मानव सभ्यता के हित में आज भी बेहद प्रासंगिक हैं महात्मा गांधी के अनमोल विचार, बस जरूरत है कि हम उन पर बात बनाने की जगह अपने रोजमर्रा के आचरण में वास्तव में अमल करने की शुरूआत करें

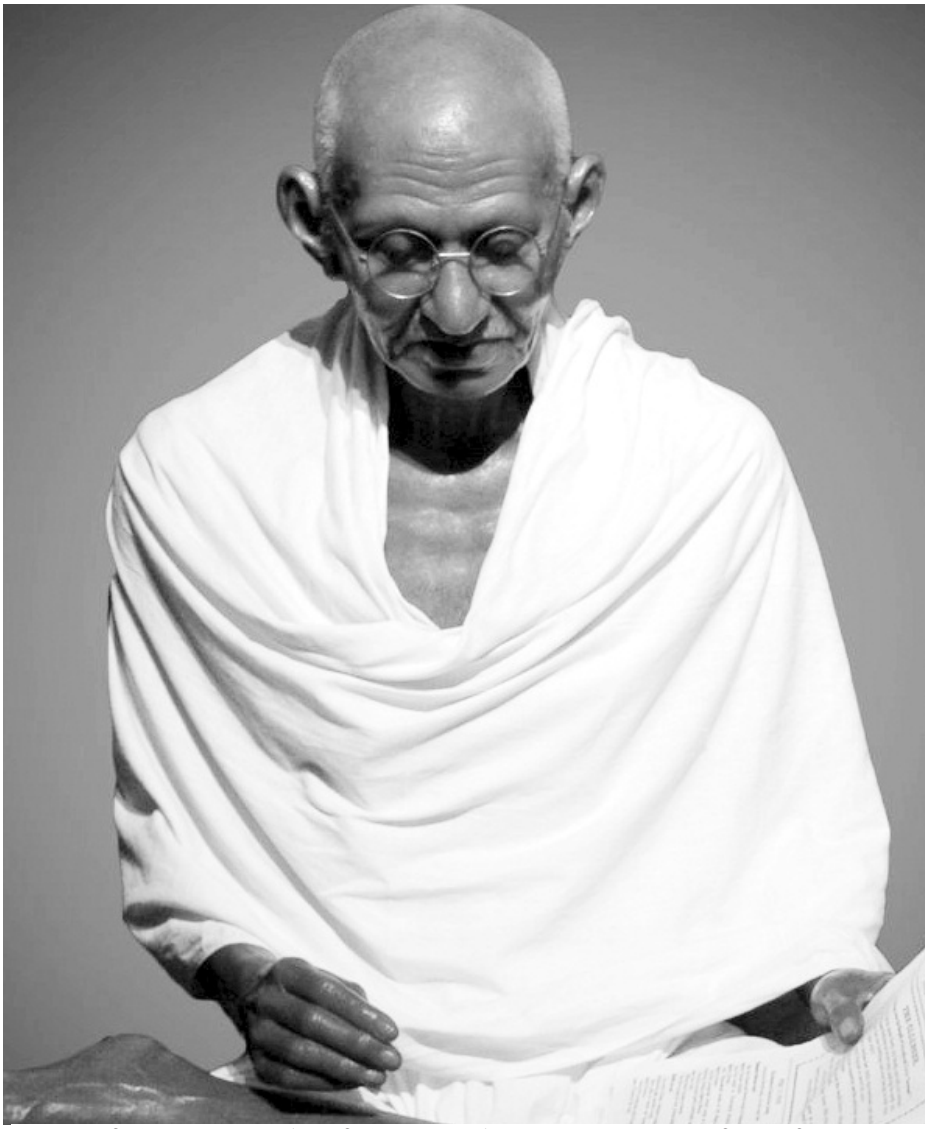

आज भी बेहद प्रासंगिक हैं गांधी के विचार और सिद्धांतहालांकि यह भी जिंदगी का एक बेहद कटु सत्य है कि महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में बात बनाना बेहद आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बेहद कठिन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य-अहिंसा के पुजारी थे, वो उसका अपने रोजमर्रा के आचरण में अक्षरशः पालन करते थे, जो कि बहुत कठिन कार्य है। वैसे भी देखा जाये तो महात्मा गांधी जी ताउम्र साक्षात, दूरगामी सोच वाले महामानव, सादगी, सरलता, सज्जनता, प्रकृतिप्रेमी, सत्य, अहिंसा, स्पष्टवादिता, समय का पालन करने वाले, धर्यवान, स्वच्छता प्रेमी, जबरदस्त संकल्प शक्ति, छूआछूत मिटाने वाले, कुटीर उद्योग के पक्षधर, स्वदेशी के पक्षधर, नस्लभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले, मान-सम्मान, स्वाभिमान, शालीनता, देश का गौरव बढ़ाने वाले, दृढसंकल्प, सहिष्णुता, मानसिक मजबूती, निडरता, आपसी भाईचारा निभाने वाले, इंसानियत को सर्वोपरि मानने वाले, करुणा, जीव प्रेम, ईमानदारी व देश प्रेम आदि बहूमूल्य गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति थे।

कोविड के चलते सर्दियों में वायु प्रदूषण बन सकता है बड़ी परेशानी का सबब

विशेषज्ञों ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इस साल सर्दियों में वायु प्रदूषण के स्तरों में संभावित बढ़ोत्तरी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने आगाह किया है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का असर कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में और इजाफे के तौर पर सामने आ सकता है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो डॉक्टर संतोष हरीश का कहना है कोविड-19 संक्रमण के हालात बदतर होने के खतरे के मद्देनजर इस साल सर्दियों में वायु प्रदूषण के स्तरों में संभावित बढ़ोत्तरी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिंता का सबब है। केंद्र तथा राज्य सरकारों को अगले दो महीने के दौरान इस मसले का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना होगा।

भारत के नामी डॉक्टर्स के संगठन द डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर के मुताबिक जहां वायु प्रदूषण की समस्या गम्भीर होती है, वहां खासकर बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। उनके लिये कोविड-19 जानलेवा हो सकता है। ऐसे में सरकार को हर साल सर्दियों में विकराल रूप लेने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये ठोस कदम उठाने ही होंगे, वरना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र खैवाल के मुताबिक चीन और इटली में किए गए अध्ययनों से यह जाहिर होता है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का असर कोविड-19 से होने वाली मौतों में वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने चेतावनी दी है कि वह पिछले दिनों संसद में विवादास्पद तरीके से कृषि विधेयक पारित कराए जाने के विरोध में इस साल पराली जलाएंगे। इससे पहले से ही खराब हालात और भी बदतर हो जाएंगे। इससे किसानों समेत हर किसी की सेहत को नुकसान होगा।

वायु प्रदूषण का विश्लेषण

सीईईडब्ल्यू और आईएआरआई के अध्ययन में भले ही वर्ष 2016 से 2019 के बीच खेतों में कृषि अवशेष या पराली जलाये जाने की दर में साल-दर-साल गिरावट दिख रही हो, मगर एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2018 और 2019 में सितम्बर और अक्टूबर के महीनों में पंजाब के 10 में से 5 जिलों में प्रदूषण के स्तर पिछले साल के मुकाबले अधिक ही रहे हैं। हरियाणा में इसकी तुलना करना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर कंटीनुअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम (सीएएक्यूएमएस) तो वर्ष 2019 में ऑनलाइन हुए हैं। पीएम10 के लिये गुरुग्राम और पीएम2.5 के लिये फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और रोहतक को छोड़ दें तो वर्ष 2018 में हरियाणा के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर सम्बन्धी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। यह अध्ययन अरबन साइंस ने कराया है।

समस्या क्या है?

भारत में खेती का शुद्ध रकबा 141.4 मिलियन हेक्टेयर है। विभिन्न फसलों की कटाई से खेत के अंदर और उनके बाहर भारी मात्रा में कृषि अवशेष (पराली) निकलते हैं। भारत में निकलने वाली पराली की सालाना अनुमानित मात्रा लगभग 60 करोड़ टन है। इसमें उत्तर

प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। यहां कुल बायोमास का 17.9% हिस्सा निकलता है। इसके बाद महाराष्ट्र (10.52%), पंजाब (8.15%), और गुजरात (6.4) प्रतिशत की बारी आती है।एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 14 करोड़ टन कृषि अवशेष जलाए जाते हैं। यह पराली खरीफ की फसल की कटाई के दौरान निकलती है। इसे जलाए जाने से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में जबरदस्त वायु प्रदूषण फैलता है।

एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हर साल तीन करोड़ 90 लाख टन भूसा जलाया जाता है।

1980 के दशक के शुरू में फसल उगाने की तर्ज में व्यापक बदलाव और भूगर्भीय जलस्तर में खतरनाक दर से गिरावट साफ नजर आने लगी थी। हालांकि पंजाब ने सूरजमुखी और मक्का की फसलों की खेती को बढ़ावा देकर विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के चलन के मद्देनजर धान की रोपाई को तरजीह दी। उसी समय खेती के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की नीति की भी खासी आलोचना की गई क्योंकि मुफ्त बिजली मिलने से भूगर्भीय जल का और ज्यादा दोहन होने लगा। पंजाब में एक किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 5337 लीटर पानी की जरूरत होती है। जाहिर है कि पंजाब भूगर्भीय जल का जबरदस्त दोहन कर रहा है।

भूगर्भीय जलस्तर में खासी गिरावट के मद्देनजर राज्य सरकार ने अत्यधिक दोहन में कमी लाने और धान की रोपाई में देर करने के लिए एक प्रशंसनीय नीति लागू करके अप्रैल-मई की छोटी अवधि में उगाई जाने वाली साथी फसल पर रोक लगा दी।

पानी बचाने की फौरी जरूरत के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉयल वॉटर एक्ट और हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉयल वाटर एक्ट लागू किया। इसके जरिए मानसून की शुरूआत से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि भूगर्भीय जल को बचाया जा सके। इन नीतियों की वजह से धान की रोपाई का समय 1 जून से आगे बढ़कर 20 जून हो गया (प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो यह घटकर 13 जून हो गया)। धान की रोपाई में की गई इस करीब एक पखवाड़े की देर से पंजाब ने 2000 अरब लीटर पानी बचाया। धान की रोपाई में एक पखवाड़े की देर से फसल कटाई में निश्चित रूप से विलंब हुआ है लेकिन इससे ऐसे समय में पराली जलाने पर भी रोक लगी है जब दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हवा की रफ्तार मद्धिम हो जाती है।

इस बीच, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर (आईआईटी-के) की अगुवाई में सेटेलाइट डाटा के इस्तेमाल से किए गए एक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि पराली जलाने के समय में करीब 10 दिन की देर होने से वर्ष 2016 में मॉनसून के बाद के मौसम में (दिल्ली के ऊपर 3%) हवा की गुणवत्ता को बदतर होने से रोकने में कुछ मदद जरूर मिली (दिल्ली के ऊपर 3%)। हालांकि अगर पराली जलाने के काम को और ज्यादा टाला जाएगा तो दहन स्रोत क्षेत्र (जैसे कि लुधियाना) और दिल्ली के लिए हवा की गुणवत्ता क्रमशः 30% और 4.4% और खराब हो सकती है। पूर्व के वर्षों के हालात, पराली जलाने के समय में बदलाव के पड़ने वाले असर में खासी अंतर वार्षिक परिवर्तनशीलता को उजागर करते हैं। साथ ही पीएम 2.5 के संकेंद्रण की तीव्रता और दिशा भी मौसम संबंधी खास हालात पर निर्भर करते हैं, इसलिए मॉनसून के बाद सिंधु गंगा के मैदानों में वायु की गुणवत्ता, मौसम विज्ञान और उत्तर-पश्चिमी भारत के खेतों में जलाई जाने वाली पराली की मात्रा के लिहाज से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। आईआईटीके ने यह अध्ययन यूनिवर्सिटी आफ लीसेस्टर, किंग्स कॉलेज लंदन पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के सहयोग से कराया है। इस अध्ययन से यह जाहिर होता है कि मौसमी चक्र से इतर जलाई जाने वाली पराली की मात्रा और उसे जलाने के इलाके में पिछले करीब दो दशक के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। खेती का रकबा बढ़ने के सरकारी आंकड़ों में इसका अक्स नजर आता है। वर्ष 2009 में भूगर्भीय जल संरक्षण नीति लागू होने के बाद से कृषि अवशेष या पराली जलाए जाने के काम में देर संभव हुई है और इसकी वजह से भूजल स्तरों पर सकारात्मक असर भी पड़ा है लेकिन जलाई जाने वाली पराली की मात्रा में भी वृद्धि हुई है और मानसून के बाद वायुमंडलीय गतिशीलता से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की वजह से इसमें साल दर साल अतिरिक्त बदलाव हो रहा है। हवा की गति बहुत धीमी हो जाने की वजह से मौसमी वायु संचार की रफ्तार बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से वायु को प्रदूषित करने वाले तत्व हवा की सतह पर ठहर से जाते हैं और इसी बीच पराली जलाए जाने की वजह से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्व पूरे सिंधु गंगा के मैदान की फिजा में पीएम2.5 की परत चढ़ा देते हैं।

पराली जलाए जाने की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए नीतिगत कदम

वर्ष 2014 में कृषि मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू (एनपीएमसीआर) नामक नीति बनाई थी और इससे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा था। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं- 1)- कृषि अवशेषों के अनुकूलतम इस्तेमाल और खेत में ही उनके निस्तारण की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, 2)- कृषि पद्धतियों के लिए समुचित मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देना, 3)- राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एनआरएसए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की मदद से पराली के निस्तारण पर नजर रखने के लिए सेटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना और 4)- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए विचारों और परियोजना प्रस्तावों के लिए विभिन्न मंत्रालयों में बहु विषयक दृष्टिकोण और फंड जुटाकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

आर्थिक मामलों से जुड़ी एक कैबिनेट समिति ने मार्च 2018 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि अवशेषों के खेत में ही निस्तारण संबंधी कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तहत 1151.80 करोड रुपए मंजूर किए थे, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हो और कृषि मशीनरी पर अनुदान दिया जा सके। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2020 में 16000 हैप्पी सीडर्स सामने आए हैं। हालांकि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर सीडब्ल्यू द्वारा कराए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 5683000 एकड़ क्षेत्र में पराली जलाई जाती है और इस रकबे में इस नुकसानदेह गतिविधि को रोकने के लिए करीब 35000 हैप्पी सीडर्स की जरूरत होगी। बहरहाल, कृषि अवशेषों के खेत में ही निस्तारण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन के निर्माण का कार्य वर्ष 2018 में मांग के मुकाबले काफी पीछे था। इन मशीनों की कोई मानक किराया दर नहीं है। इसके अलावा ऐसी प्रौद्योगिकियों की किराया दरें भी कुछ किसानों के लिये बहुत ऊंची हैं। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसानों के लिए ऐसी मशीनों पर धन खर्च करना काफी महंगा साबित होता है जिन्हें साल के कुछ ही दिनों में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी महीनों में वे बेकार खड़ी रहती हैं।

हालांकि वर्ष 2019 में सरकार की सोच बदली और उसने माना कि सिर्फ प्रौद्योगिकी उपायों से ही पराली जलाए जाने की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। पंजाब और हरियाणा में सरकार ने एक नीति बनाई जिसके तहत किसानों को पराली नहीं जलाने और उसका वैकल्पिक तरीके से निस्तारण करने के लिए ढाई हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की पेशकश की गई, मगर दुर्भाग्य से यह घोषणा नवंबर के आखिरी हफ्ते में की गई। उस वक्त तक काफी मात्रा में पराली जलाई जा चुकी थी। अनेक पंचायतों ने इसके दुरुपयोग की शिकायत की जिसके बाद इस साल इस योजना को पूरी तरह रद्द कर दिया गया।

नीति विशेषज्ञों द्वारा बार-बार सुझाए जाने वाले दीर्घकालिक समाधान

विशेषज्ञों ने खेती के तौर-तरीके और तर्ज में विविधता लाने और बेतहाशा पानी की जरूरत वाली धान की फसल को छोड़कर मक्का अन्य फसलें उगाने को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया है। पंजाब ने धान की जगह सूरजमुखी और मक्का की खेती करने की कोशिश की थी मगर यह प्रयोग बेहद अनमने ढंग से किया गया था, लिहाजा नाकाम साबित हुआ। द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के एक अध्ययन पत्र में कहा गया है कि सिंधु गंगा के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों में रोटेशन का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। इसके लिए किसानों को धान गेहूं फसल प्रणाली के अलावा अन्य फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंजाब और हरियाणा में भूगर्भीय जल संकट को देखते हुए कृषि विविधीकरण की दिशा में प्रयास जारी हैं। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके राज्य में धान की फसल का कोई भविष्य नहीं है। विविधीकरण की इस कोशिश में कोविड-19 महामारी से पैदा हुई अव्यवस्था के कारण और तेजी आई है। जून-जुलाई में धान की रोपाई के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर उपलब्ध न होने की वजह से मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती के रकबे में और ज्यादा इजाफा हुआ है। इस रूपांतरण को बनाए रखना और इन फसलों को बाजार में न सिर्फ जगह दिलाना बल्कि उनके वाजिब दाम दिलाना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सामूहिक दुष्कर्म दरिंदगी की हद

सामूहिक दुष्कर्म (बलात्कार) ने दरिंदगी की हद पार कर दी शर्मसार की प्रकाष्ठा पार हुआ। गया, बिहार गया के कोर्स थाना अंतर्गत पड़ोस में जन्मदिन पार्टी से लौट रही एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है दुष्कर्म से पीड़ित किशोरी ने लोक लाज के भय से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली 2 अक्टूबर को पीड़िता के परिजनों ने तीन नामजद व एक अज्ञात युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई घटना 29 सितंबर की रात की है जब वह जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रही थी तभी कुछ मनचलों ने जबरन उसके साथ मुंह काला किया देर रात घर वापसी पर उसकी तबीयत बिगड़ गई उन्होंने उसके इलाज के लिए पटना ले गए। इलाज करा कर 1 अक्टूबर को घर लेकर आए तो किशोरी ने मौका देखकर घरवालों के नजरों से बचाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वाले लाश को लेकर थाने पहुंच गए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया सबको भेज दिया ।

थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी एससी एक्ट के तहत दर्ज की गई है एससी एसटी के थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने इस बात की पुष्टि करते हुए त्वरित कार्रवाई की बात कही।उन्होंने कहा कि पोस्ट थाना के बलवा ग्राम में किशोरी के साथ हुए यौन शोषण का मुख्य आरोपी चंदन यादव को एसटीएफ ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है आरोपी ने अकेले में पिता से मिलने की बात स्वीकारी है घटना की रात की फोन से पिता को चंदन ने बुलाया था। इस घटना में तीन अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण के आरोप की पुष्टि अभी नहीं हुई है दूसरी ओर ग्रामीणों में चर्चा है कि जन्मदिन पार्टी में शामिल कुछ मनचले पहले से ही ताक लगाकर उस पर बैठे हुए थे पार्टी से बाहर निकलते ही अंधेरी गली में घसीट कर उस किशोरी की अस्मत लूट ली गई। अभी मामला आया है कि किशोरी मेनिनजाइटिस बीमारी से ग्रसित थी एसपी व डीएसपी वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं पुलिस द्वारा लगातार छापामारी के बावजूद भी आरोपी फरार बताया गया ।

दुस्साहस 2

अभी एक दर्द से पोस्ट थाना उबरा भी नहीं था तभी शनिवार 2 अक्टूबर को इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया । इस नए मामले में पिता ने तीन लोगों क्रमशः विकास यादव मिथिलेश राम चंदन राम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गुनाहगार अभी भी फरार है पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात पति खेत पर पटवन करा रहे थे वह औरत पति के लिए खाना लेकर खेत पर गई थी खाना खिलाने के बाद घर लौटने के क्रम में तीन लोगों ने गांव के पुलिया पर उसे रोका फिर हाथ पकड़ लिया और बारी बारी से अपना मुंह काला किया। पति के देर रात मैं खेत पर रहने के कारण सुबह को थाना में इसकी सूचना दी गई। आरोपी ने महिला से दुष्कर्म कर थाने नहीं जाने की धमकी दी थी और कहा था कि थाना को बताने पर पति और तुम्हारी जान ले लेंगे घटना की सूचना पाते ही टिकारी के डीएसपी नागेंद्र सिंह ने वारदात की तहकीकात में जुट गए पीड़िता

को मेडिकल जांच और 164 के तहत बयान दर्ज कर ली गई है ।

दुस्साहस 3

मगध विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत मटिहानी गांव में गुरुवार की देर रात एक मंदबुद्धि बालिका के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया युवक को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को आरोपी सुरेंद्र मांझी ने एक मंद बुद्धि नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया ।आरोपी दो बच्चे के पिता भी हैं शुक्रवार को ही आरोपी को जेल भेज दिया गया पीड़िता के परिजनों ने बताया कि रात में वह घर से बाहर निकली थी तभी सुरेंद्र मांझी ने उसे जबरन पकड़कर घटना को अंजाम दिया । उपरांत गांव के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया तथा थाना को सूचना दी और आरोपी पकड़ा गया। नाबालिक को मेडिकल जांच हेतु भेज दिया गया बलात्कार की घटना से गया एवं बोधगया का पावन भूमि शर्मसार हो गया है

दुस्साहस 4

लखीसराय जिला के चानन थाना अंतर्गत 29 सितंबर की संध्या एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया गया है। 30 सितंबर को नाबालिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली नाबालिक लड़की की सहेली के भाई ने उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया वारदात के समय पीड़िता की मां और पिता जमुई जिला के झाझा शहर गए हुए थे।

स्वजनों ने बताया कि लड़की घर में अकेली थी इसी दौरान उसकी सहेली का भाई रामप्रवेश कुमार उर्फ राजा उसे बुलाने आया उसने कहा कि उसकी सहेली उसे बुला रही है जब लड़की अपनी सहेली के नए घर में पहुंची वहां कोई नहीं था वहां राजा ने दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी बुधवार को माता-पिता जब घर वापस पहुंचे तो देखा कि बेटी बीमार की तरह लेटी हुई और रो रही थी ।उसने घटना के बारे में दोनों को बता दीया। लड़की के माता-पिता ने लड़के के अभिभावक से शिकायत करते हुए पुलिस को भी सूचना दी लौटने पर उन्होंने देखा कि लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली घटना की सूचना मिलते ही चानन थाना अध्यक्ष वैभव कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित राजा के पिता राजेश पासवान बाहर नौकरी करते हैं जानकी देवी में आरोपित अपनी मां और बहन के साथ रहता है इस मामले में मृत लड़की के पिता ने राजा और उसकी मां मंजू देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है घटना के बाद आरोपित अपने परिवार के साथ घर से फरार है।

दुस्साहस 5

गया जिला के चंदौसी थाना अंतर्गत एक वाहन चालक अवधेश यादव ने घर में विधवा मालकिन के साथ यौन शोषण किया और फरार हो गया यह वारदात शनिवार की रात को घटित हुई इस संबंध में चंदौसी थाना मैं प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो इस कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया चंदौसी थाना अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह ने बताया कि विधवा द्वारा यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वाहन चालक को कुछ माह पहले कुछ ना पहले ही रखा था। बाद में उसके बदचलनी के कारण काम से हटा दिया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी पर शिकंजा कसते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र कईचन गांव स्थित उसके घर से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में 164 के तहत मामला दर्ज कराते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

आक्रोश मार्च कैंडल मार्च एवं मौन जुलूस

गया में हाथरस कांड ,कोच थाना कांड ,बोधगया दुष्कर्म कांड के विरोध में नेशनल ह्यूमन राइट एवं पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट स्वावलंबन एवं राष्ट्रीय जनता दल ने आक्रोश मार्च कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला।

विरोध करता राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सुशासन बाबू) के शासन काल में महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म पर विरोध जताया। मार्च का नेतृत्व जयंत चाणक्य, गणेश सिंह, सुप्रिया ,सालनी कुमारी ,मधु कुमारी ,शारदा देवी इंदु देवी ,रूबी देवी, राजन पांडे संजय कुमार राजद के संजय यादव संतोष कुमार, रवि पासवान चंदन यादव दिव्यांश यादव, महेंद्र यादव कर रहे थे।

देश एवं राज्य राजयो में बढ़ते दुष्कर्म एवं महिलाओं पर अत्याचार पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए लोगों ने कहा कि पीड़ित महिला को मुआवजा एवं आरोपित को कठोर दंड दिया जाए। हाथरस कांड में मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की एवं दुर्व्यवहार प्रजातंत्र के लिए घातक एवं कुठाराघात है बिहार प्रेस मेंस यूनियन ने हाथरस उत्तर प्रदेश में मीडिया कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की है साथ ही इस दुष्कर्म में शामिल सभी आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है।

रामविलास का राजनीतिक जीवन, दलितों को समर्पित...

देश के दिग्गज दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान कई सप्ताह से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। यहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

समाजवादी आंदोलन के स्तंभों में से एक थे राम विलास पासवास

छोड़ी थी पुलिस सेवा

खगड़िया जिला के शहरबन्नी गांव में जन्में रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज, खगड़िया से स्नातक एवं पटना विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद 1969 में उनका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ लेकिन उन्हें पुलिस सेवा में नहीं जाना था इसलिए डीएसपी जैसे पद को छोड़ कर पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एमएलए बने।

इसके बाद 1970 में पासवान एसएसपी के संयुक्त सचिव बनाए गए। पांच साल बाद इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध करने पर उन्हें जेल जाना पड़ा और 1977 में जेल से रिहा हुए। इसके बाद उन्हें 1985 में लोकदल का महासचिव बनाया गया। इसके बाद पासवान ने 1987 में जनता दल का महासचिव पद संभाला।

मिलनसार पासवान

पासवान काफी मिलनसार और दोस्ताना लहजे वाले रहे थे। शुरूआत से ही राजनीति में जयप्रकाश नारायण, कपूर्री ठाकुर, राजनारायण और सत्येंद्र नारायण सिन्हा से पासवान की काफी नजदीकियां रहीं थीं। पासवान दूरदर्शी थे इसलिए 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ तब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त वो जानते थे कि एनडीए का पतन होना शीघ्र है। उन्होंने यह देख लिया था कि बीजेपी और बसपा साथ होने जा रही है जिसकी वजह से मायावती को यूपी सीएम का पद मिला। इसी गठबंधन में 2004 में पासवान को केंद्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया और उन्होंने फिर एक बार इस्पात मंत्रालय का भी प्रभार संभाला। लेकीन डायरेक्ट फॉरेन इंवेस्टमेंट के मसले को लेकर उन्होंने यूपीए 2012 में छोड़ दिया।

बीजेपी से गठबंधन

नरेंद्र मोदी के कमान संभालते ही पासवान की लोजपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली और लोजपा को इससे 6 सीट मिली। इसके साथ ही रामविलास पासवान नौंवी बार चुनाव जीत गए। इसके बाद उन्हें कैबिनेट में उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिला और एक बार फिर उन्हें राज्य सभा का सदस्य बनाया गया। इस तरफ रामविलास पासवान को 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला।

दलितों के एकछत्र नेता

इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और तभी से दलित मतदाताओं को लुभाने की राजनीति शुरू हो गई। दलित पैंथर के 1972 में बनने के बाद से दलित वोट बैंक बनना शुरू हुआ। 1977 में चुनाव होने थे लेकिन उससे पहले ही जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ गए। उनके जाते ही दलितों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा लेकिन इसी दौरान कानपुर और लखनऊ में दलितों की नाराजगी बढ़ गई। फिर जब कांशीराम नेता बन उभरे तब दलित पैंथर और बामसेफ जैसे संगठनों को बल मिला। मायावती 2014 का चुनाव हार गईं वरना यह दलित बल बना रहता। उधर बिहार में रामविलास पासवान ने दलितों और दूसरी जातियों के साथ मिल कर राजनीति की। भोला पासवान शास्त्री और रामसुंदर दास की लोकप्रियता कम हुई और रामविलास बिहार के दलितों के एकछत्र नायक बने।

महिला शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए सम्पूर्ण रूप से कार्य कर रहीं है ज्योति शर्मा

मिसेज इंडिया गोल्डन पर्सनालिटी ली डिवाइन कम्पनी से क्लासिक केटेगरी विनर 2020 ज्योति शर्मा महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं। अलीगढ़ की बेटी ज्योति जी ने देश का नाम रोशन किया है। महिला सशक्तीकरण व दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही ज्योति जी के सिर मिसेज इंडिया गोल्डन पर्सनालिटी क्लासिक केटेगरी विनर 2020 का ताज सजा। इसके साथ ही वह एक बहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी है। वह एक कर्मठ महिला है और ऐसी कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही है जिनकी कोई पहचान नही बन पाई है। इन्होंने इस छेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

वहीं ज्योति जी को ऐसे कई उपलब्धियों के लिए भी सम्मानित किया गया है। ज्योति जी बताती हैं जब वह मिसेज इंडिया कांटेस्ट के ऑडिशन के लिए गईं तो काफी घबराई हुईं थीं, पर हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार जीत हासिल हुई। हिम्मत हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बैठाकर यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने मे लगी हुई है।

भारत की जानी-मानी ली डिवाइन कम्पनी में भी सहयोग कर रही है। समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही ज्योति जी महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उन्होंने महिला समूहों के माध्यम से कई उपलब्धिया एवं मुहिम छेड़ी है। घरेलू हिंसा और महिलाओं पर होने वाली अन्य ज्यादतियों को रोकने के वह लगातार जनजागरण कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयास रंग लाने लगे हैं। वह महिलाओ के लिए हमेशा खड़ी नजर आती है।

ज्योति जी महिला शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए सम्पूर्ण रूप से कार्य कर रहीं है। अब शासन, प्रशासन के स्तर पर भी उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। यही इनके जीवन का लक्ष्य है।

आयुर्वेद की अहमियत

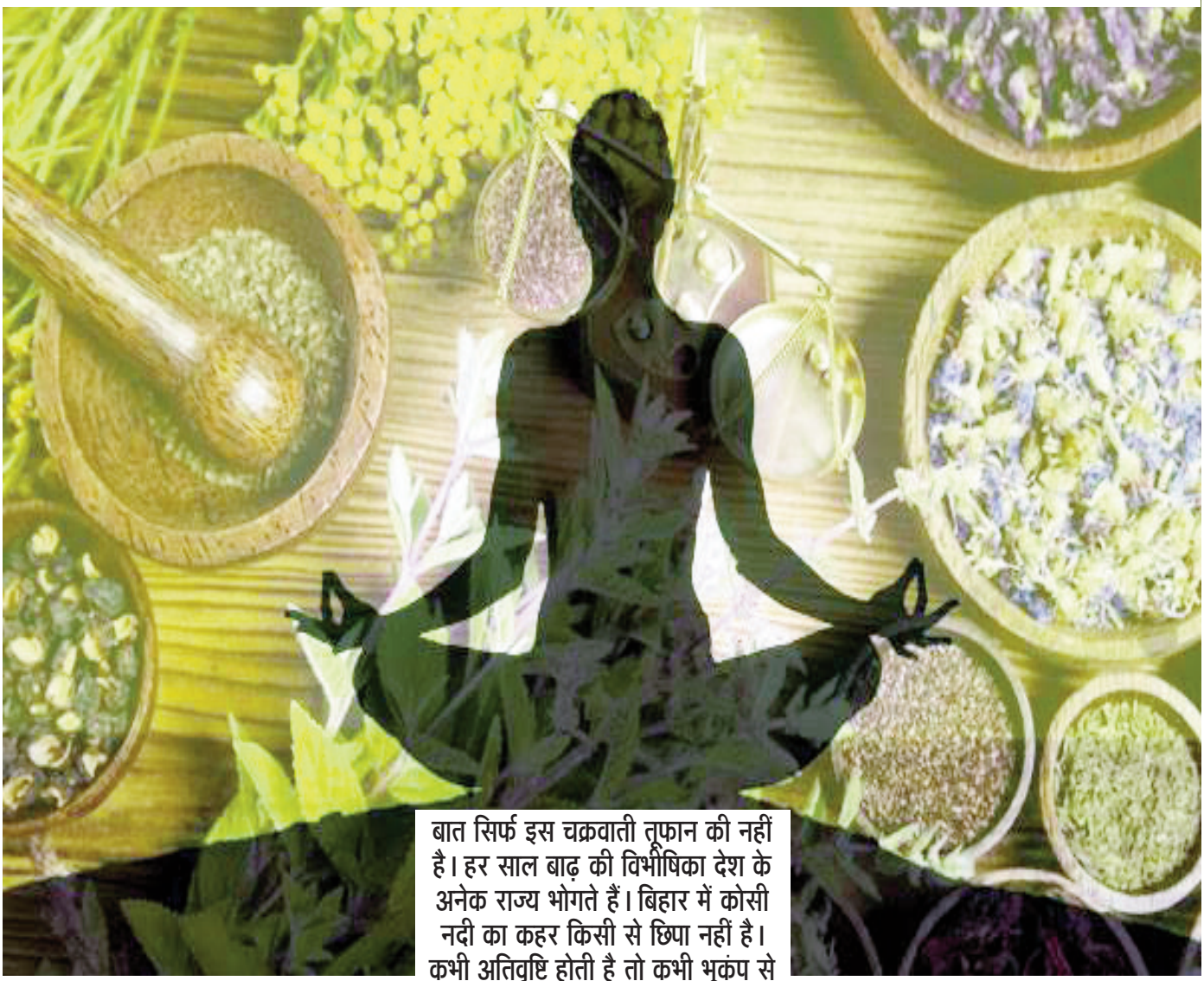

बात सिर्फ इस चक्रवाती तूफान की नहीं है। हर साल बाढ़ की विभीषिका देश के अनेक राज्य भोगते हैं। बिहार में कोसी नदी का कहर किसी से छिपा नहीं है। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी भूकंप से धरती थरार्ती है, तो कभी अल्पवर्षा का भोगमान देश के किसानों को भोगना पड़ता है। केदारनाथ में मची तबाही लोगों के जेहन में अभी ताजा ही होगी। यह बात आईने की तरह साफ है कि इस तरह के नियम कायदे कानून बनाए जाने से शायद परिवर्तन आने वाला नहीं है। इस तरह की कवायदों से तो महज कागजों पर ही आपदा प्रबंधन होता दिखता है। आलम यह होता है कि जब भी किसी तरह की आपदा सर पर आती है तब हमारे हुक्मरान जागते हैं।

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भारत सरकार ने देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को मान्यता देकर महामारी से निपटने की दिशा में अतिमहत्वपूर्ण कदम उठाया है।स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसके लिए तौर तरीकों संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनसे अब सम्पूर्ण भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से कोरोना संक्रमण का इलाज संभव हो सकेगा।मार्च 2020 से अब तक के कोरोना अवधि में संक्रमितों के इलाज के लिए सिर्फ ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर हीं निर्भरता बनी हुई थी।संक्रमण चाहे हल्का हो या ज्यादा,हर मरीजों को नियम के अनुकूल सरकारी या निजी अस्पतालों में जांच के बाद एकांतवास में भेंजा जा रहा था।फलस्वरूप लोगों के दिलोदिमाग में कोरोना को ले खौफ ज्यादा बन गया और लोगों द्वारा संक्रमण को छुपाया जाने लगा।हालांकि सरकार होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को भी इस तरह की मान्यता दे चुकी है।बहरहाल सम्पूर्ण देश में जिस तरह से लाखों लोग कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति के साथ हालात से निपटना संभव नहीं है।दरअसल महामारी घोषित होने के बाद भारत सहित विश्व के तमाम देशों के समक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप चलने की बाध्यता रही है,इसलिए भारत में देसी चिकित्सा पद्धतियों को कोई तवज्जो नहीं मिली।हालांकि लोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों का प्रयोग करते रहे और कोई संदेह नहीं कि देसी नुस्खे बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है।

आयुर्वेद भारत हीं नहीं दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है।धन्वंतरि से लेकर चरक,सुश्रुत जैसे आयुर्वेद को ऋषियों ने मानव जाति के लिए हर प्रकार से

समृद्ध बनाया गया।रोगों के निदान से लेकर औषधि के निर्माण तक में यह पद्धति अब तक जारी है,इसका बड़ा प्रमाण है कि भारत आज आयुर्वेद चिकित्सा के बड़े केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित हो चुका है।बड़ी बात है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में आयुर्वेद,होमियोपैथ,सिद्ध,योग जैसी चिकित्सा पद्धतियां काफी सस्ती होने के कारण आम लोगों की पहुंच में है।भारतीय घरों में आमतौर पर रसोई में इतनी चीजें उपलब्ध रहती है जिन्हें ज्यादातर बीमारियों में अचूक औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है,इसलिए कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेद चिकित्सक पहले से हीं मास्क एवं सुरक्षित दूरी के उपाय के अलावा हल्दी,लौंग,सौंठ,काली मिर्च,दालचीनी जैसे मिश्रण का काढ़ा पीने की सलाह देते रहे जिससे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो और संक्रमण से सुरक्षित रहें।आयुर्वेद में विश्वास का प्रतिफल है कि देशभर में करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया है जो सकारात्मक भी रहा है।

देश की एक बड़ी आबादी महंगी ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है।कोरोना संक्रमण से जंग में लोग अब आयुर्वेद की अहमियत को मान्यता मिल जाने के कारण सस्ते में इलाज करवा पाएंगे।हालांकि आयुर्वेद का इलाज फिलहाल हल्के व मध्यम श्रेणी के संक्रमितों के लिए हीं है,गंभीर मामलों में इलाज ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से हीं करवाना होगा।कोरोना का टीका जब आएगा तब आएगा लेकिन तब तक एवं उसके बाद भी कोरोना से जंग में आयुर्वेद हीं बड़ा व सार्थक हथियार साबित होगा।

मार्च 2020 से अब तक के कोरोना अवधि में संक्रमितों के इलाज के लिए सिर्फ ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर हीं निर्भरता बनी हुई थी।संक्रमण चाहे हल्का हो या ज्यादा,हर मरीजों को नियम के अनुकूल सरकारी या निजी अस्पतालों में जांच के बाद एकांतवास में भेंजा जा रहा था।फलस्वरूप लोगों के दिलोदिमाग में कोरोना को ले खौफ ज्यादा बन गया और लोगों द्वारा संक्रमण को छुपाया जाने लगा।हालांकि सरकार होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को भी इस तरह की मान्यता दे चुकी है।बहरहाल सम्पूर्ण देश में जिस तरह से लाखों लोग कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति के साथ हालात से निपटना संभव नहीं है।दरअसल महामारी घोषित होने के बाद भारत सहित विश्व के तमाम देशों के समक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप चलने की बाध्यता रही है,इसलिए भारत में देसी चिकित्सा पद्धतियों को कोई तवज्जो नहीं मिली।हालांकि लोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों का प्रयोग करते रहे और कोई संदेह नहीं कि देसी नुस्खे बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है।

नये शिक्षक से होगा राष्ट्र का नवनिर्माण

यह शिक्षकों के योगदान के प्रति आभार जताने का दिन भी है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका भले ही बदली हो, लेकिन उनका महत्व एवं व्यक्तित्व-निर्माण की जिम्मेदारी अधिक प्रासंगिक हुई है। क्योंकि सर्वतोमुखी योग्यता की अभिवृद्धि के बिना युग के साथ चलना और अपने आपको टिकाए रखना अत्यंत कठिन होता है। फौलाद-सा संकल्प और सब कुछ करने का सामर्थ्य ही व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है- आत्मा, मस्तिष्क, वाणी और कर्म-इन सबके विकास में संतुलन बना रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सर्वांगीण विकास का अर्थ है- हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक एवं गुरु आचार, संस्कार, व्यवहार और विचार- इन सबका परिमार्जन एवं विकास करने का प्रयत्न करते रहते थे। जबकि मैकाले की शिक्षा विद्यार्थी को शरीर, मन, बुद्धि एवं चरित्र से रुग्ण बनाकर केवल धन कमाने की मशीन, कुसंस्कृत एवं पतनोन्मुख बनाती रही है। राजनीतिक संघर्ष से भले ही देश को शारीरिक स्वतंत्रता मिली पर विगत सात दशकों में मानसिक-बौद्धिक-भावात्मक परतंत्रता की बेड़िया मजबूत हुई है।

विश्व शिक्षक (अध्यापक) दिवस प्रतिवर्ष दुनिया के लगभग एक सौ देशों में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया को परिष्कृत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण करने में शिक्षकों के प्रयासों और कड़ी मेहनत की सराहना और स्वीकार करने के अवसर के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत के लिये यह दिवस इसलिये महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है जिसमें शिक्षकों को अधिक सशक्त, जिम्मेदार एवं राष्ट्र- व्यक्ति निर्माण में उनकी भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। लार्ड मैकाले की शिक्षा में अब तक भारत में गुरु एवं शिक्षक श्रद्धा का पात्र न होकर वेतन-भोगी नौकर बन गया था, शिक्षक की भूमिका गौण हो गयी थी। आजादी के बाद से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में विद्यालय एवं विश्व विद्यालय के प्रबंध तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी और शिक्षालय मिशन न होकर व्यवसाय बन गया था। इस बड़ी विसंगति को दूर करने की दृष्टि से वर्तमान शिक्षा नीति में व्यापक चिन्तन-मंथन किया गया है।

जब साल 1994 से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाना शुरू हुआ तब हर साल के शिक्षक दिवस की एक थीम चुनी जाती है। इस दिवस का मुख्य

उद्देश्य एक छात्र की जिंदगी में शिक्षकों के महत्व को रेखांकित करना है। यह शिक्षकों के योगदान के प्रति आभार जताने का दिन भी है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका भले ही बदली हो, लेकिन उनका महत्व एवं व्यक्तित्व-निर्माण की जिम्मेदारी अधिक प्रासंगिक हुई है। क्योंकि सर्वतोमुखी योग्यता की अभिवृद्धि के बिना युग के साथ चलना और अपने आपको टिकाए रखना अत्यंत कठिन होता है। फौलाद-सा संकल्प और सब कुछ करने का सामर्थ्य ही व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है- आत्मा, मस्तिष्क, वाणी और कर्म-इन सबके विकास में संतुलन बना रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सर्वांगीण विकास का अर्थ है- हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक एवं गुरु आचार, संस्कार, व्यवहार और विचार- इन सबका परिमार्जन एवं विकास करने का प्रयत्न करते रहते थे। जबकि मैकाले की शिक्षा विद्यार्थी को शरीर, मन, बुद्धि एवं चरित्र से रुग्ण बनाकर केवल धन कमाने की मशीन, कुसंस्कृत एवं पतनोन्मुख बनाती रही है। राजनीतिक संघर्ष से भले ही देश को शारीरिक स्वतंत्रता मिली पर विगत सात दशकों में मानसिक-बौद्धिक-भावात्मक परतंत्रता की बेड़िया मजबूत हुई है। अब नरेन्द्र मोदी सरकार ने शिक्षा की इन कमियों एवं अधूरेपन को दूर करने के लिये नयी शिक्षा नीति घोषित की है और उसमें शिक्षकों के दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें जिम्मेदार, नैतिक-चरित्रसम्पन्न नागरिकों का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गयी है।

भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर दिमाग का राष्ट्र बन गया है, तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि उसके लिये तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो कोई फर्क पा सकते हैं वे पिता, माता और शिक्षक हैं।ह्व डॉ. कलाम की यह शानदार उक्ति प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में आज भी गूंज रही हैं। शिक्षण इस दुनिया में सबसे प्रेरक काम और एक बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक ज्ञान का भंडार हैं जो अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देने में विश्वास करते हैं जिससे उनके शिष्य भविष्य में दुनिया को बेहतर बनाने में सहायता कर सकेंगे। इससे ऐसी पीढ़ी निर्मित होगी जो उज्ज्वल और बुद्धिमान हो तथा वह जो दुनिया को उसी तरीके से समझे जैसी यह है और जो भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों से प्रेरित हो। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, शिक्षक देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी वजह से वे अधिक सम्मान के योग्य होते हैं। नयी शिक्षा नीति में ऐसी संभावनाएं है कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रभावी बनकर प्रस्तुत होगी। अब शिक्षा से मानव को योग्य, राष्ट्र-निमार्ता एवं चरित्रवान बनाने का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। अब शिक्षक एवं शिक्षा-नीति एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर अग्रसर हुई है। जिस तरह एक शिल्पकार प्रतिमा बनाने के लिए जैसे पत्थर को कहीं काटता है, कहीं छांटता है, कहीं तल को चिकना करता है, कहीं तराशता है तथा कहीं आवृत को अनावृत करता है, वैसे ही अब हर शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यक्तित्व को तराशकर उसे महनीय और सुघड़ रूप प्रदान करेंगे। हर पल उनकी शिक्षाएं प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में, संस्कार के रूप में जीवंत होंगी। अब शिक्षक अपने विद्यार्थी की निषेधात्मक और दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करके नया जीवन प्रदान करेंगे। वरुण जल का देवता होता है। जैसे जल वस्त्र आदि के मैल को दूर करता है, वैसे ही शिक्षक विद्यार्थी की मानसिक कलुषता को दूर कर सद्संस्कारों का बीजारोपण करेंगे एवं उसके व्यक्तित्व को नव्य और स्वच्छ रूप प्रदान कर सकेंगे। चन्द्रमा सबको शांति और आह्लाद प्रदान करता है, वैसे ही शिक्षक की प्रेरणाएं विद्यार्थी को मानसिक प्रसन्नता और परम शांति दे सकेगी। यानी शिक्षक एवं शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य अब प्राप्त होगा। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में -व्यक्तित्व-निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है। निःस्वार्थी और जागरूक शिक्षक ही किसी दूसरे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। हाल ही में आपने सुपर-30 फिल्म में एक शिक्षक के जुनून को देखा। इस फिल्म में प्रो. आनन्द के शिक्षा-आन्दोलन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुति दी गयी है। अब नयी शिक्षा नीति से ऐसे ही आन्दोलनकारी शिक्षा उपक्रम जगह-जगह देखने को मिलें, तभी इस नवीन घोषित शिक्षा नीति की प्रासंगिकता है।

अनेकानेक विशेषताओं के बावजूद अब तक शिक्षक का पद धुंधला रहा था। जैसाकि महात्मा गांधी ने कहा था-एक स्कूल खुलेगी तो सौ जेलें बंद होंगी। पर उल्टा होता रहा है। स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ जेलों के स्थान छोटे पड़ते गये हैं। जेलों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। स्पष्ट है- हिंसा और अपराधों की वृद्धि में मैकाले की शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षक भी एक सीमा तक जिम्मेदार है। अशिक्षित और मूर्ख की अपेक्षा शिक्षित और बुद्धिमान अधिक अपराध करते रहे हैं। वह अपने पापों और दोषों पर आवरण डालने हेतु अधिक युक्तियां सोचने में सक्षम बने। इस स्थिति के लिये शिक्षक ही जिम्मेदार रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो तनाव, टकराव और बिखराव की घटनाएं घटित होती रही हैं, उसके मूल में संकीर्णता और ईर्ष्या की मनोवृत्ति भी एक बड़ा कारण है।

विरोध सिर्फ पंजाब-हरियाणा में ही क्यों, बिहार-यूपी में क्यों नहीं

इस सप्ताह लोक सभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन अहम विधेयक पारित हुए, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा में जबर्दस्त विरोध देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं.लेकिन बीते साल किसान मार्च के लिए चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र और तीन साल पहले किसानों के हिंसक आंदोलन के लिए खबरों में रहे मध्यप्रदेश और दूसरे राज्यों से कृषि बिल के विरोध की खबरें कम ही मिल रही हैं.क्या वाकई कुछ राज्यों को छोड़ कर अन्य जगहों पर इन तीन विधेयकों का उतना विरोध नहीं हो रहा? और अगर वाकई ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है?इन तीनों बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. जहां विपक्ष इन बिलों को किसान विरोधी बता रही है वहीं सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में हैं.इसके विरोध में पंजाब में खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया है. हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई दी है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है.

विपक्ष के आरोप

विपक्ष का आरोप है कि सरकार कृषि मंडी की व्यवस्था हटाना चाहती है जिससे देश की खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी. इसके साथ सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित रखना चाहती है.हालांकि विपक्ष के इस विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आश्वासन दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी.लेकिन किसान उनके आश्वासन संतुष्ट हुए नहीं लगते. मोदी के उन्हें भरोसा दिलाने के बाद भी वो सड़कों पर हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं.

मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.

किसानों के मुद्दे और विरोध

कृषि मामलों के जानकार हरवीर सिंह कहते हैं कि कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज होने की वजह का नाता वहां की राजनीति और किसान संगठनों से तो है ही साथ ही अनाज खरीद की सरकारी व्यवस्था से भी है.वो बताते हैं, अगर किसान आंदोलन के इतिहास को देखें तो आपका पता चलेगा कि आंदोलन का केंद्र ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है.वो कहते हैं, रही महाराष्ट्र की बात तो वहां आंदोलन अधिकतर पश्चिमी हिस्से में दिखते हैं जहां गन्ने और प्याज की खेती होती है. मध्यप्रदेश में आंदोलन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है. वहां कभी किसानों के मजबूत संगठन नहीं रहे हैं. लेकिन वहां भी मंडियों में इसका विरोध हुआ है और मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल की है.महाराष्ट्र में किसान बड़ा वोटबैंक है लेकिन यहां गन्ना किसान अधिक हैं और गन्ने की खरीद के लिए फेयर एंड रीमुनरेटिव सिस्टम (एफआरपी) मौजूद है और उसका मूल्य तय करने के लिए शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर अभी भी है. उत्तर प्रदेश में भी काफी जमीन हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल होने लगी है जिसका एमएसपी से कोई लेना-देना नहीं है.ऐसे में जहां किसानों पर इन बिल का सीधा असर पड़ रहा है वहां किसान सड़क पर आ गए हैं लेकिन जहां ये सीधे तौर पर किसानों को प्रभावित नहीं कर रहे वहां विरोध उतना अधिक नहीं दिख रहा.

कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये सवाल है कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं तो ये समझिए कि उन्हें ये लगता है कि ये उनके हित में नहीं है. लेकिन बाजार इसका विरोध नहीं कर रहा क्योंकि इससे उन्हें लाभ है.

वो समझाते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की समस्याएं, मुद्दे और उनकी राजनीति अलग है इसलिए उनके विरोध को देखने का तरीका भी बदलना होगा. सरकार जो अनाज की खरीद करती है उसका सबसे अधिक हिस्सा यानी करीब 90 फीसदी तक पंजाब और हरियाणा से होता है. जबकि देश के आधे से अधिक किसानों को ये अंदाजा ही नहीं है कि एमएसपी क्या है. ऐसे में उन्हें ये समझने में वक्त लगेगा कि उनकी बात आखिर क्यों हो रही है.देविंदर शर्मा कहते हैं, ये समझने की जरूरत है कि जिस पर सीधा असर होगा वो सबसे पहले विरोध करेगा. एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6 फीसदी किसानों को एमएसपी मिलता है. लेकिन 94 फीसदी किसानों को तो पहले ही एमएसपी नहीं मिलता और वो बाजार पर निर्भर हैं. ऐसे में ये समझा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध क्यों कर रहे हैं.वो कहते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगातार संकट से जूझता रहा है लेकिन कुछ ही किसान हैं जो इस संकट से बचे हुए हैं. वो कहते हैं, जिन 6 फीसदी किसानों को एमएसपी मिलता है वो संकट से बचे हुए हैं क्योंकि उनकी आय निश्चित हो जाती है.पंजाब और हरियाणा में राजनीति किसानों से जुड़ी है और इस कारण वहां पार्टियों के लिए किसानों के पक्ष में आना मजबूरी हो गया है.ये समझने के लिए आपको देखना होगा कि कहां क्या खेती होती है और कहां से सरकार अधिक अनाज खरीदती है. ऐसे में अधिकतर राज्यों में किसानों को ये मुद्दा सीधे तरीके से प्रभावित नहीं करता.

लेकिन इसका बड़ा असर छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा. मुझे लग रहा है कि कई राज्यों में आने वाले दिनों में आंदोलन तेज हो सकता है.

वो समझाते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की समस्याएं, मुद्दे और उनकी राजनीति अलग है इसलिए उनके विरोध को देखने का तरीका भी बदलना होगा. सरकार जो अनाज की खरीद करती है उसका सबसे अधिक हिस्सा यानी करीब 90 फीसदी तक पंजाब और हरियाणा से होता है. जबकि देश के आधे से अधिक किसानों को ये अंदाजा ही नहीं है कि एमएसपी क्या है. ऐसे में उन्हें ये समझने में वक्त लगेगा कि उनकी बात आखिर क्यों हो रही है.देविंदर शर्मा कहते हैं, ये समझने की जरूरत है कि जिस पर सीधा असर होगा वो सबसे पहले विरोध करेगा. एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6 फीसदी किसानों को एमएसपी मिलता है. लेकिन 94 फीसदी किसानों को तो पहले ही एमएसपी नहीं मिलता।

एसएसपी और किसान

एनएसएसओ की साल 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 फीसदी से भी कम किसान अपने उत्पाद एमएसपी पर बेचते हैं. वहीं भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के अनाज खरीदने की व्यवस्था का लाभ न तो अधिक किसानों तक और न ही अधिक राज्यों तक पहुंचा है.किसानों से सरकार जो अनाज सबसे अधिक खरीदती है उनमें गेहूं और चावल शामिल है और अगर अनाज की खरीद के आंकड़ों के देखा जाए तो ये स्पष्ट

होता है कि राज्य के कुल उत्पादन और खरीद के मामले में पंजाब और हरियाणा की स्थिति दूसरों से काफी बेहतर है.खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में पंजाब और हरियाणा में हुए कुल धान उत्पादन का 80 फीसदी सरकार ने खरीदा, जबकि गेंहू के मामले में इन दो राज्यों से कुल उत्पादन का 70 फीसदी से अधिक सरकार ने खरीदा. लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है. दूसरे राज्यों में कुल उत्पादन का छोटा हिस्सा सरकार खरीदती रही है और किसान वहां पहले से ही बाजार पर निर्भर करते रहे हैं.

बिहार और बाजार का मामला

बिहार देश का पहला वो राज्य था जिसने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 2006 में एपीएमसी एक्ट (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी यानी कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति) को खत्म कर दिया था. यहां इसके बाद निजी सेक्टर के लिए रास्ता साफ कर दिया गया.लेकिन राज्य को वाकई लाभ पहुंचा ऐसा कहा नहीं जा सकता. स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड 2013 के अनुसार इससे वहां कृषि उत्पाद बेचने की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और छोटे किसानों की निर्भरता बाजार पर बढ़ गई है.

आइडियाज फॉर इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2001-02 से लेकर 2016-17 तक बिहार की कृषि विकास दर देश की औसत कृषि विकास दर से कम रही है. रिपोर्ट के अनुसार, एपीएमसी के हटाए जाने के बाद यहां धान, गेहूं और मक्का की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन किसानों की आय में अनिश्चितता भी उतनी ही अधिक बढ़ी. साथ ही कीमतों में भी अनिश्चितता बरकरार रही जिससे किसानों को ये समझ नहीं आया कि कितनी जमीन पर कितनी खेती करें तो उन्हें नुकसान नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार यही अनिश्चितता शायद वहां के कृषि विकास की दर कम होने का कारण बनी.हाल में जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया तो मजदूरों का पलायन शुरू हुआ.

पलायन करने वाले अधिकांश मजदूर बिहार से ही थे और इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है.अगर हम ये मानें कि देश के 94 फीसदी किसान एमएसपी पर नहीं बाजार पर निर्भर करते हैं तो ये भी समझिए कि बाजार को अगर किसानों को लाभ पहुंचाना ही होता तो बीते 70 सालों में किसानों की स्थिति सुधर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो इस बात की ओर इशारा है कि बाजार किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता.वो कहते हैं,इन तीनों बिल के साथ सरकार पंजाब के किसान जो अभी एमएसपी के कारण बेहतर स्थिति में हैं उन्हें बिहार के किसानों के स्तर तक ले आएगी, जो लगातार बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.वो कहते हैं, सरकार ने बिल बनाने से पहले किसानों से राय ली नहीं है और उन्हें बाजार के भरोसे छोड़ दिया है.

एमएसपी और खाद्य सुरक्षा से इसका नाता

भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए खाद्य संकट से जूझने के लिए 1942 में खाद्य विभाग बनाया गया था. आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को इसे

बिहार देश का पहला वो राज्य था जिसने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 2006 में एपीएमसी एक्ट (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी यानी कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति) को खत्म कर दिया था. यहां इसके बाद निजी सेक्टर के लिए रास्ता साफ कर दिया गया.लेकिन राज्य को वाकई लाभ पहुंचा ऐसा कहा नहीं जा सकता. स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड 2013 के अनुसार इससे वहां कृषि उत्पाद बेचने की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और छोटे किसानों की निर्भरता बाजार पर बढ़ गई है. आइडियाज फॉर इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2001-02 से लेकर 2016-17 तक बिहार की कृषि विकास दर देश की औसत कृषि विकास दर से कम रही है.

खाद्य मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया. 1960 में इस मंत्रालय के तहत दो विभाग बने खाद्य विभाग और कृषि विभाग.खाद्य विभाग पर सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनाज खरीदने का काम सौंपा गया. आजादी के बाद पहली बार 60 के दशक की शुरूआत में देश को गंभीर अनाज संकट का सामना करना पड़ा. इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई गईं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरूआत की गई. इसके बाद अनाज खरीदने के लिए सरकार ने 1964 में खाद्य निगम कानून के तहत भारतीय खाद्य निगम बनाया और इसके एक साल बाद एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया ताकि उचित कीमत पर (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों ने अनाज खरीदा जा सके. इसी अनाज को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस) के तहत सरकार जरूरतमंदों को देती है और खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज का भंडारण भी करती है. जहां तक बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की है भारत में ये व्यवस्था राशन सिस्टम की तरह थी जो आजादी से पहले भी कुछ शहरी इलाकों तक सीमित थी. लेकिन 1951 में इसे देश की सामाजिक नीति का हिस्सा बनाया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार गांवों तक किया गया. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका दायरा और बढ़ा दिया गया. एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनने के बाद पीडीएस की स्थिति और अहम हो गई क्योंकि इससे एक तरफ किसानों को निश्चित आय मिलने का भरोसा मिला, दूसरी तरफ जरूरतमंदों को कम कीमत में अनाज की सुविधा मिली और तीसरी तरफ खाद्य सुरक्षा बेहतर हुई.

क्या इन तीनों बिल का व्यापक असर हो सकता है?

शांता कुमार समिति की रिपोर्ट, मुझे जितना समझ आ रहा है, किसानों में ये डर है कि अगर ये बिल अस्तित्व में आ जाते हैं तो एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा और इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट की बात करते हुए अनाज खरीदने की पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर सकती है.इनमें से किसी बिल में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है लेकिन ये बिल कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले बड़े सुधारों की दिशा में एक कदम हैं जो सरकार के विजन का एक हिस्सा है.

शांता कुमार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को इन-काइंड यानी अनाज की खरीद की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बजाय कैश ट्रांसफर पर ध्यान देना चाहिए. और इस बिल से जुड़ी व्यापक तस्वीर या कहें लार्जर नैरेटिव यही है. इन बिल को उस प्रक्रिया को शुरू करने की कवायद की तरह देखा जा रहा है और ये चिंता का विषय है.मुझे इसकी चिंता उतनी अधिक नहीं है जितनी इस बात की है कि इसके जरिए एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा और अनाज का मूल्य तय करने वाली एक पूरी व्यवस्था के न रहने का बड़ा असर किसानों पर हो सकता है. क्योंकि किसानों के लिए कीमतों का कोई बेंचमार्क ही नहीं रहेगा और ऐसे में बाजारों पर उनकी निर्भरता कहीं अधिक बढ़ जाएगी.शांता कुमार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार की तरफ से अनाज खरीदने के लिए भी कह सकती है इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता वितरण प्रणाली पर कुछ असर पड़ेगा.

जून 2019 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि एफसीआई को लेकर शांता कुमार के सुझावों को लागू करना सरकार की प्राथमिकताओं में से है.सरकार इस दिशा में बढ़ सकती है इसका संकेत उस वक्त भी मिला था जब इसी साल जून में मोदी सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कवरेज को 70 फीसदी से घटा कर 20 फीसदी तक लाया जाना चाहिए, और अनाज की खरीद कम कर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तरफ बढ़ना चाहिए. कुछ यही शांता कुमार कमिटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है.

वो तीन कृषि विधेयक जिनका हो रहा है विरोध?

इसी सप्ताह लोकसभा में सरकार के प्रस्तावित तीन विधेयक पास हुए हैं- पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, दूसरा, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और तीसरा, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020.

पहला बिल एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी.

दूसरा बिल कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए है. ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है. तीसरे में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है. माना जा रहा है कि इस विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी.

लोजपा के 'राम' का दुनिया को अलविदा

* 1969 में पासवान ने लड़ा था पहला चुनाव
* रामविलास पासवान का जन्म 05 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था।
* बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की।
* 1969 में पहली बार पासवान बिहार के राज्यसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीते।
* 1977 में छठी लोकसभा में पासवान जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने।
* 1982 में हुए लोकसभा चुनाव में पासवान दूसरी बार जीते।
* 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया तथा 1989 में नौवीं लोकसभा में तीसरी बार चुने गए।
* 1996 में दसवीं लोकसभा में वे निर्वाचित हुए।
* 2000 में पासवान ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जन शक्ति पार्टी का गठन किया।
* इसके बाद वह यूपीए सरकार से जुड़ गए और रसायन एवं खाद्य मंत्री और इस्पात मंत्री बने।
* पासवान ने 2004 में लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
* बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोकसभा में भी चुनाव जीते।
* अगस्त 2010 में बिहार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और कार्मिक तथा पेंशन मामले और ग्रामीण विकास समिति के सदस्य बनाए गए थे।

रामविलास पासवाने भारतीये दलिते राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, वे लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधने की सरकार में केन्द्रीय मंत्री भी थे।

वे सोलहवीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में निधन हो गया।

पासवान का पारिवरिक सफर

बिहार के खगडिया जिले के शहरबन्नी गाँव के रहने वाले हैं। वह अनुसूचित जाति परिवार के लिए पैदा हुये थे। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी किये थे। 2014 में उन्होंने खुलासा किया था कि लोकसभा नामांकन पत्रों को चुनौती देने के बाद उन्होंने 1981 में उन्हें तलाक दे दिया था।

उनकी पहली पत्नी राजकुमारी से उषा और आशा दो बेटियां हैं। 1983 में, अमृतसर की एयरहोस्टेस और

पंजाबी हिन्दू रीना शर्मा से विवाह कर लिए थे। रीना शर्मा से एक बेटा और एक बेटी है। बेटो चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिरागे एक अभिनेता से राजनीति में आये हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हो गया।

श्री पासवान पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से नौ जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन इस बार सत्रहवीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामलों के मंत्री पद की शपथ ली। श्री पासवान के पास छः प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी रहा है।

चिराग ने ट्वीट से दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

राष्ट्रपति ने दूरदर्शी बताया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। रामविलास पासवान संसद के सबसे अधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मेंबर रहे। वे दलितों की आवाज थे और उन्होंने हाशिये पर धकेल दिए गए लोगों की लड़ाई लड़ी।

चिराग अंत तक साथ रहे

चिराग पासवान ने इस विषम परिस्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है और, पिता रामविलास नहीं रहे। चिराग ने अपने पिता का अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ा। बीते दो महीने से, यानी जब से बिहार चुनावों की गहमागहमी शुरू हुई, तब भी चिराग पिता के पास दिल्ली में मौजूद रहे। जब पासवान की तबियत बिगड़नी शुरू हुई, उसके बाद से चिराग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं गए। एक बार दिल्ली के महावीर मंदिर गए, जहां उन्होंने पिता के लिए प्रार्थना की। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बावजूद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। इंटरव्यू नहीं दिया और ना मीडिया में बयानबाजी की। लगातार अस्पताल और घर के बीच ही दौड़ते रहे। पार्टी की अहम बैठकों में भी केवल मौजूदगी के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों को पिता की बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी देते रहे।

कुछ दिन पहले ही हुई थी पासवान की हार्ट सर्जरी

रामविलास पासवान पिछले करीब एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात को उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। यह पासवान की दूसरी हार्ट सर्जरी थी। इससे पहले भी उनकी एक बायपास सर्जरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन कर केंद्रीय मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।

जहाँ और भी है सितारों के आगे

बॉलीवुड और विवादों का एक मजबूत रिश्ता है। चाहे बात कास्टिंग काउच, पतनशीलता, भाई-भतीजावाद, पूर्वाग्रह या उच्च और पराक्रमी के संबंधों के बारे में हो, बॉलीवुड ने निश्चित रूप से वैश्विक मीडिया में लंबे समय तक केंद्र के मंच पर कब्जा कर लिया है। अब, एक बार फिर, मनोरंजन उद्योग खुद को नशीली दवाओं की लत और डिबेंचरी सरफेसिंग के आरोपों के साथ वैश्विक टकटकी में पाता है। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा ड्रग्स में बॉलीवुड की भागीदारी के बारे में दावे किए जाने के बाद इस बार विवाद बढ़ गया।

अभिनेत्री ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि बॉलीवुड में 90% नशा करने वाले हैं। इसी ट्वीट में, कंगना ने कोकीन एडिक्ट होने के नाते इंडस्ट्री में कुछ बड़े नामों का भी खुलासा किया। अभिनेत्री ने यह भी दावा किया कि ड्रग्स की बात होने पर पुलिस और राजनेता भी भागीदार होते हैं। एनसीबी बॉलीवुड में इसके खरीदारों, ड्रग पहुंचाने वालों और सप्लायर्स के साथ उन लोगों का पता लगा रही है जो इस धंधे को चला रहे हैं। इसकी उभरती हुई तस्वीर यह है कि बॉलीवुड के कई पूर्व और मौजूदा एक्टर्स एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं।

बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन काफी पुराना है. कई सितारे इसके लती होकर बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके मायाजाल से खुद को मुक्त कर लिया. फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे एक्टर संजय दत्त को कभी बॉलीवुड के ड्रग किंग कहा जाता था. ड्रग्स और शराब के सेवन ने उनको भीतर से खोखला कर दिया था. अमेरिका में जब उनका इलाज हो रहा था तो डॉक्टर्स ने उन्हें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स की एक लिस्ट थमाई थी ताकि वो बताएं कि उसमे से उन्होंने किस किस का सेवन किया है. डॉक्टर्स यह देख कर हैरान थे कि संजय ने सभी पर निशाँ लगा दिए यानी उन्होंने उस लिस्ट में मौजूद हर ड्रग का सेवन किया था. आखिर तब ये ड्रग्स उन तक कैसे पहुँचती थीं? हालांकि अमेरिका में इलाज के बाद संजय ने शानदार वापसी की और जबरदस्त बॉडी भी बनाई और उन्हें एहसास हो गया कि जिंदगी से बड़ा नशा कोई नहीं है. लेकिन आज वह फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं .

रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह संगीत की दुनिया में इतने हिट हुए कि सफलता सर चढ़कर बोलने लगी और इसकी मस्ती में वे ड्रग्स और शराब के एडिक्ट हो गए. इसके बाद से ही हनी सिंह के गाने आने बंद हो गए थे और वे रिहैब सेंटर भी गए. लम्बे समय तक अपने चाहने वालों से दूर रहने के बाद हालांकि हनी सिंह ड्रग्स से जंग जीतकर वापसी कर चुके हैं और अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दे रहे हैं. आज का बॉलीवुड वैसे भी देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों को छोड़कर पूरी तरह नंगा हो चुका है एकाद फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्मे हम परिवार के साथ नहीं देख सकते. बच्चों की मानसिकता पर नंगापन, नशा और मर्डर जैसे सीन हावी हो रहें है जिनका उनकी असल जिंदगी पर असर हो रहा है.

यही कारण है कि आज हमारा समाज पूरी तरह फिल्मी हो चुका है. हम जीवन मूल्यों की कदर करना भूल गए है क्योंकि हमें परोसी ही गंदगी जा रही है.मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि बॉलीवुड को कभी भी नैतिक रूप से उच्च भूमि के रूप में नहीं देखा गया है, हाल की घटनाओं ने उद्योग के साथ भारतीय मध्यम वर्ग के मोहभंग को स्वीकार किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मन ब्रांड्स के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 18-30 साल की उम्र में 82% युवाओं ने कहा कि एक सेलिब्रिटी द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग ने उन्हें 'अविश्वसनीय'वे इस तरह के एक सेलिब्रिटी द्वारा समर्थित ब्रांड नहीं खरीदेंगे। युवा देश की संपत्ति है और नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति सबसे संवेदनशील वर्ग यही है। इसलिये, सख्त बहुआयामी रणनीति अपनाकार इस खतरे को रोकने का प्रयास करना चाहिए। निसंदेह इस प्रकरण ने बॉलीवुड का काला सच सामने लाने का प्रयास किया है. भाई-भतीजावाद, खानदानी रुतबा,काले पैसे,कास्टिंग काउच, शारीरिक शोषण जैसे कारनामे बॉलीवुड की देन है. जिस दुनिया में कदम रखने के लिए आज के युवा सब कुछ करने को तैयार है, उसकी काली सच्चाई सब को दहला रही है. बॉलीवुड सितारों का युवा पीढ़ी और बच्चों पर सीधा असर पड़ता है. इनकी नशे बाजी भी इन पर असर छोड़ती है. बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन आम है और कास्टिंग काउच जरूरत. इन सब को जानकर अब युवा पीढ़ी को अपना मन जरूर बदल लेना चाहिए. तलाश करनी चाहिए एक साफ-सुथरे क्षेत्र में सुनहरे भविष्य की जहाँ वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके. सितारों के आगे जहाँ और भी है.